पेज 02

झीरम हमले में 10 दोषी, मास्टरमाइंड से पूछताछ नहीं

साप्ताहिक

शहर सत्ता

PRGI NO. CTHIN/25/A2378

सोमवार, 07 सितंबर से 13 सितंबर 2026

हम दिखाएंगे आईना...

पेज 08

सड़कों पर घूमते मवेशी दावों के बीच सिस्टम लाचार

वर्ष : 02 अंक : 27 पृष्ठ : 08 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com

पेज 04 खुरचन : मकानों में कारोबार, गली-मोहल्लों में बाजार

इलाज चाहिए तो इंतजार करिए

एम्स और अम्बेडकर अस्पताल का नाम बड़ा और सुविधा नाममात्र

पेट सीटी स्कैन के लिए डेढ़ से तीन महीने की लंबी वेटिंग

विकास यादव
प्रमुख संवाददाता

छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) रायपुर और प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी डॉ. भीमराव आंबेडकर अस्पताल (अम्बेकर अस्पताल) में इलाज की स्थिति चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। डॉक्टर और स्टाफ की भारी कमी, बेड का अभाव और लंबी वेटिंग लिस्ट के चलते मरीजों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्थिति यह है कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को सर्जरी और जरूरी जांचों के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे कई बार मरीजों की जान पर भी बन आती है।

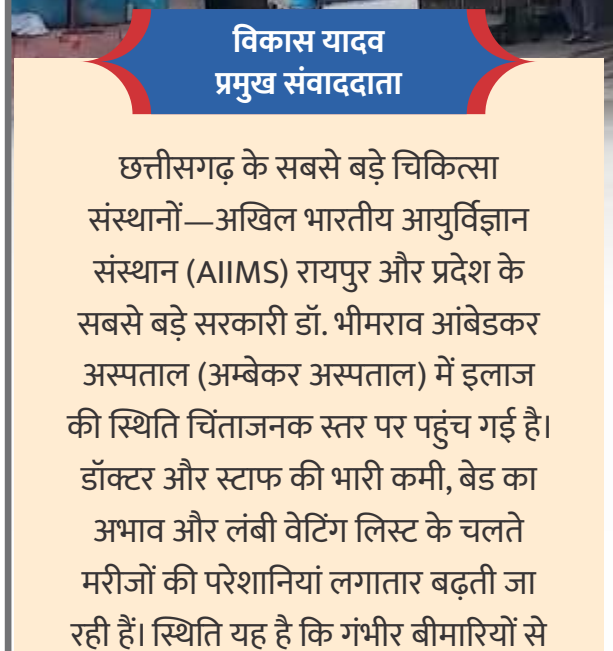

दिल्ली एम्स की घटना और रायपुर के हालात

हाल ही में एम्स नई दिल्ली में 15 साल की तन्वी के हार्ट में छेद का ऑपरेशन 15 साल बाद भी न होने के कारण 1 सितंबर को हुई मौत का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एम्स रायपुर में मरीजों की परेशानी का एक बड़ा कारण जटिल प्रोटोकॉल और लंबी कागजी प्रक्रिया है। मरीज को ऑपरेशन से पहले जरूरी जांच के लिए इतने चरणों से गुजरना पड़ता है कि कई बार इस दौरान मरीजों की शारीरिक स्थिति बिगड़ने लगती है। आंबेडकर अस्पताल में प्रक्रिया थोड़ी तेज है, लेकिन यहाँ भी रेडियोग्राफर की कमी के चलते एमआरआई जांच 24 घंटे उपलब्ध नहीं है; यह केवल ओपीडी टाइम या इमरजेंसी में ही संभव हो पाती है।

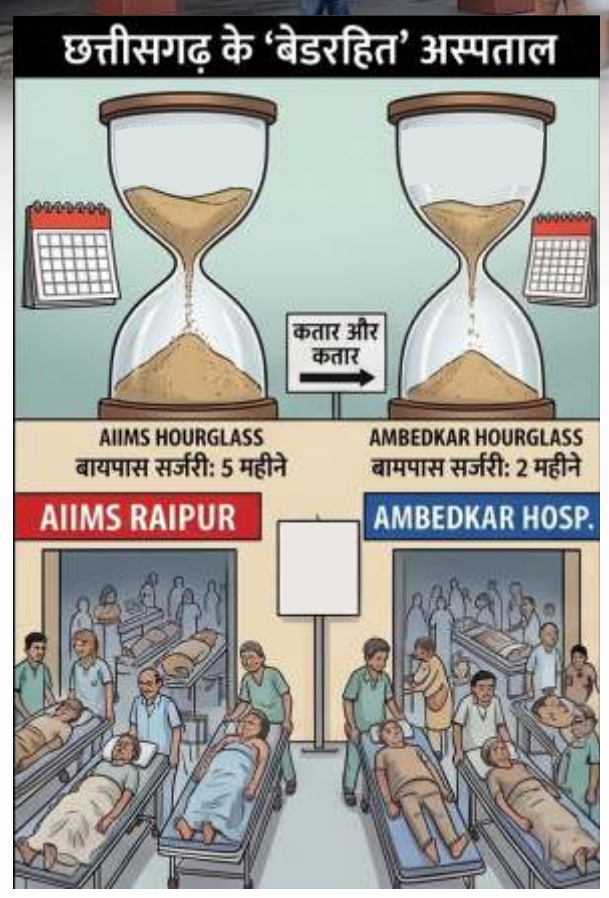

छत्तीसगढ़ के 'बेडरहित' अस्पताल

बायपास सर्जरी के लिए 4 से 5 महीने का लंबा इंतजार

राजधानी के दोनों प्रमुख सरकारी अस्पतालों में हृदय रोगियों के लिए स्थिति बेहद दयनीय है:

- **AIIMS रायपुर:** यहाँ हार्ट की बायपास सर्जरी के लिए 4 से 5 महीने की लंबी वेटिंग चल रही है।
- **अम्बेकर अस्पताल (ACI):** पं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट (ACI) में बायपास सर्जरी के लिए 2 महीने की वेटिंग है, जो एम्स के मुकाबले थोड़ी कम है लेकिन फिर भी मरीजों के लिए भारी कष्टदायक है।

सोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए तरस रहे मरीज

सर्जरी तो दूर, इलाज से पहले की जाने वाली बुनियादी और गंभीर जांचों के लिए भी मरीजों को महीनों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है:

AIIMS में भारी वेटिंग: एम्स रायपुर में सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई और पेट सीटी (PET-CT) जांच के लिए डेढ़ से तीन महीने (45 से 50 दिन) का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

एसीआई (अम्बेकर) की स्थिति: इसके विपरीत, एसीआई में सोनोग्राफी, सीटी स्कैन व एमआरआई के लिए महज 2 से 3 दिनों की वेटिंग है। वहीं, आंबेडकर अस्पताल प्रबंधन सीटी-एमआरआई और सोनोग्राफी में 'जीरो वेटिंग' का दावा करता है, हालांकि धरातल पर प्रक्रिया पूरी होने में 2 से 3 दिन लग ही जाते हैं।

प्रशासन और प्रबंधन का पक्ष

एम्स के पीआरओ डॉ. मृत्युंजय राठौर ने इस स्थिति पर सफाई देते हुए कहा है: "एडवांस और क्वालिटी इलाज के लिए सभी विभागों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि कुछ विशेष सर्जरी और जांचों के लिए मरीजों को इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि, इमरजेंसी सेवाओं में तत्काल जांच और इलाज की पूरी सुविधा उपलब्ध है, और वेटिंग सूची में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है।"

बड़ा सवाल: कब सुधरेगी व्यवस्था?

एम्स और आंबेडकर अस्पताल में डॉक्टरों-स्टाफ की कमी, बेड का अभाव और महीनों लंबी वेटिंग ने छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है। सवाल यह है कि क्या सरकार और अस्पताल प्रबंधन जल्द ही इन संसाधनों को बढ़ाकर आम जनता को राहत दे पाएगा, या मरीजों को इसी तरह इलाज के लिए दर-दर भटकना पड़ेगा?

वीआईपी कल्चर और 'अप्रोच' का खेल

दोनों ही बड़े सरकारी अस्पतालों में आम मरीजों और रसूखदारों के इलाज के बीच बड़ा फर्क साफ दिखाई देता है:

वीआईपी को तुरंत राहत: वीआईपी या सिफारिश (अप्रोच) से आने वाले मरीजों को जांच के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। हाल ही में एक डॉक्टर को पेट सीटी जांच के लिए एम्स ले जाया गया, जहाँ उनकी जांच तुरंत हो गई, जबकि आम मरीजों को हफ्तों कतार में खड़ा रहना पड़ता है।

मजबूरी में बाहर जाना: सरकारी दरों पर जांच सस्ती होने (जैसे आंबेडकर में सोनोग्राफी 100 रुपए या आयुष्मान कार्ड पर फ्री) के कारण गरीब मरीज यहीं आने को विवश हैं, लेकिन भारी वेटिंग उनके जीवन पर भारी पड़ रही है।

पेट सीटी स्कैन: एम्स में 7 हजार फीस और 50 दिन की वेटिंग, निजी में 25 हजार खर्च

सरकारी अस्पतालों में केवल एम्स रायपुर में ही पेट सीटी (PET-CT) स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, जो मुख्य रूप से कैंसर के मरीजों के लिए बेहद जरूरी होती है।

एम्स: यहाँ पेट सीटी जांच का शुल्क महज 7,000 रुपए है, जो निजी अस्पतालों के मुकाबले काफी कम है। कम फीस होने के कारण यहाँ 45 से 50 दिनों की लंबी वेटिंग है।

निजी अस्पताल: प्राइवेट सेंटर्स में यही जांच 22 से 25 हजार रुपए में होती है। लंबी वेटिंग और मजबूरी के चलते कई आर्थिक रूप से सक्षम मरीज निजी अस्पतालों का रुख करने को मजबूर हैं।

राजनीति की भेंट चढ़ा कैंसर सेंटर: आंबेडकर अस्पताल स्थित रीजनल कैंसर सेंटर में फरवरी 2018 से पेट सीटी व गामा कैमरा इंस्टाल है, लेकिन आपसी राजनीति और प्रशासनिक उदासीनता के चलते यह आज तक शुरू नहीं हो पाया है। यही कारण है कि मरीजों को मजबूरन भारी-भरकम फीस देकर प्राइवेट सेंटरों में जाना पड़ रहा है।

CGPSC-DMF घोटाला, उत्कर्ष और सतपाल को जेल

शहर सत्ता/रायपुर। DMF घोटाले के आरोपी सतपाल सिंह छाबड़ा और CGPSC घोटाले के आरोपी उत्कर्ष चंद्राकर को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दोनों की 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड खत्म होने के बाद शनिवार को ED ने उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया था। ED ने रिमांड बढ़ाने के लिए आवेदन नहीं दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इधर, CGPSC घोटाले की जांच में अभ्यर्थियों को परीक्षा के पेपर मुहैया कराने के नाम पर लाखों रुपए लेने की बात सामने आई है। ED के वकील सौरभ पांडेय के मुताबिक, उत्कर्ष चंद्राकर की मामले में भूमिका अभ्यर्थियों तक प्रीलिम्स और मेन्स के पेपर पहुंचाने से जुड़ी थी। CGPSC मामले की जांच को लेकर सौरभ पांडेय ने बताया कि जांच के दौरान एक महिला कैंडिडेट का बयान दर्ज किया गया है। उसके मुताबिक, उसे प्रीलिम्स परीक्षा का पेपर पहले मुहैया कराया गया था। परीक्षा में पूछे गए 100 प्रतिशत सवाल उस पेपर से मैच हुए। इसके बाद मेन्स परीक्षा का पेपर मुहैया कराने के नाम पर उससे करीब 70 लाख रुपए लिए गए। महिला को कथित तौर पर मेन्स का पेपर दिखाकर मुहैया कराया गया, लेकिन जब वास्तविक परीक्षा हुई तो वह पेपर मैच नहीं हुआ। सौरभ पांडेय के मुताबिक, जांच में ऐसे और अभ्यर्थियों से पैसे लिए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

ड्राई डे पर 14.86 लीटर से ज्यादा अवैध शराब जब्त

शहर सत्ता/रायपुर। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर शुष्क दिवस के दौरान अवैध शराब की बिक्री और परिवहन रोकने के लिए आबकारी विभाग ने जिले में कार्रवाई की। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में अलग-अलग जगहों से अवैध शराब बरामद की गई और 3 मामले दर्ज किए गए। कार्रवाई के दौरान एक कार भी जब्त की गई। पहली कार्रवाई पाजी द पिंड ढाबा में की गई। यहां ईशु पाल भसीन के कब्जे से होंडा WR-V कार में रखी अलग-अलग ब्रांड की 8 बोतल विदेशी शराब मिली। शराब की कुल मात्रा 6 लीटर थी, जिसकी कीमत करीब 15,856 रुपए आंकी गई है। शराब ले जाने में इस्तेमाल कार की कीमत करीब 6.50 लाख रुपए बताई गई है। आबकारी विभाग ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की गैर-जमानती धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया है। दूसरी कार्रवाई थाना खम्हारडीह क्षेत्र में की गई। यहां राजू मलिक के कब्जे से 21 पाव देशी मदिरा मसाला और 2 बोतल बीयर बरामद की गई। जब्त मदिरा की कुल मात्रा 5.08 बल्क लीटर और कीमत 2,580 रुपए बताई गई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई।

सर्चिंग के दौरान 30 किलो विस्फोटक बरामद, टिफिन IED नष्ट

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर में ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी की टीचर पत्नी से चाकू की नोक पर बंधक बनाकर रेप का मामला सामने आया था। इस केस में 5 साल की सुनवाई के बाद फैसला आया है। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) विनय कुमार प्रधान की अदालत ने आरोपी बालकृष्ण जांगड़े को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, आरोपी की पत्नी अंजना जांगड़े को पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक, मामला 15 मार्च 2021 का है। आरोपी बालकृष्ण जांगड़े और उसकी पत्नी अंजना जांगड़े मूल रूप से बेमेतरा के रहने वाले हैं और रायपुर के पिरदा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते थे। वारदात के समय पीड़िता अपने दो बच्चों के साथ घर पर अकेली थी। पति सुबह करीब 10 बजे ऑफिस चले गए थे। पीड़िता के अनुसार, आरोपी शादी का कार्ड देने के बहाने घर पहुंचा। उसने खुद को पति का दोस्त बताया। इसके बाद पति का परिचित होने की बात कहकर घर के अंदर घुस गया।

झीरम हमले में 10 दोषी, मास्टरमाइंड से पूछताछ तक नहीं

सरेंडर के बाद देवजी पढ़ता रहा, 12वीं की परीक्षा दी, 33 अब भी फरार

शहर सत्ता/रायपुर। 25 मई 2013 के झीरम घाटी नरसंहार मामले में 13 साल बाद जगदलपुर की स्पेशल NIA कोर्ट ने 10 नक्सलियों को दोषी ठहराया है। 11 आरोपियों में से एक की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। दोषियों की सजा पर फैसला 16 सितंबर को होगा। सीएम साय ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले का सभी को स्वागत करना चाहिए। बता दें कि, लंबे ट्रायल में 101 गवाहों के बयान दर्ज हुए और दस्तावेज और दूसरे सबूत पेश किए गए। बचाव पक्ष फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा। हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 29 लोगों की जान गई थी। हालांकि, जांच में सामने आए बड़े नामों को लेकर अब भी सवाल हैं। अभियोजकों के मुताबिक झीरम हमले के मास्टरमाइंड थिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवजी ने 24 फरवरी 2026 को तेलंगाना में सरेंडर किया था। इसके बाद उसने 12वीं की परीक्षा भी दी, लेकिन अब तक उससे पूछताछ नहीं हुई है। जांच के मुताबिक, हमले की प्लानिंग करीब 3 महीने पहले की गई थी और जंगल में कैंप बनाकर राशन जुटाया गया था। कोर्ट ने प्रमिला मोडियम, चैतू लेकाम उर्फ मुन्ना, सुमित्रा पुनेम, मोडियम मुक्का, मंडवी कोसा कवासी उर्फ कोसाराम, आयाता मरकाम, मड़ाकामी देवा, जोगा मड़ाकामी, बंजामी सन्ना उर्फ चामरू उर्फ डेंगा और महादेव नाग को दोषी माना है। मामले में नामजद कई अन्य आरोपी अब भी फरार हैं। करीब 33 आरोपी अदालत की पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे आरोपी भी हैं, जिन्होंने बाद में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना में सरेंडर कर दिया।

देवजी से अब तक पूछताछ नहीं

जांच रिकॉर्ड के मुताबिक, थिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवजी घटना के समय माओवादी संगठन की क्षेत्रीय कमान (SRUC) में सीनियर कमांडर था। वहीं, बारसे सुक्का उर्फ देवा दरभा डिवीजन कमेटी का सचिव रहा और बाद में बटालियन-1 का कमांडर बना। जांच में दोनों की भूमिका झीरम हमले से जुड़ी बताई गई है। NIA ने 23 दिसंबर 2023 को जारी वांटेड इश्तहार में देवजी और देवा समेत 19 नक्सलियों की जानकारी सार्वजनिक की थी। इसमें देवजी का नाम और फोटो भी शामिल था। देवजी ने 24 फरवरी 2026 को तेलंगाना में सरेंडर किया, जबकि देवा ने 2 जनवरी 2026 को तेलंगाना में सरेंडर किया। सरेंडर के बाद थिप्पिरी तिरुपति देवजी ने मई में इंटरमीडिएट सेकंड ईयर की तेलुगु परीक्षा भी दी थी। इसके बावजूद इस मामले में पुलिस ने अब तक उससे पूछताछ नहीं की है। इस मामले में कट्कम सुदर्शन को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन 2023 में उसकी मौत हो गई। वहीं, सबसे बड़ा वांछित आरोपी मुपल्ला लक्ष्मणा राव उर्फ गणपति अब तक पकड़ से बाहर है। घटना के समय वह CPI (माओवादी) का महासचिव था।

इन 10 नक्सलियों को ठहराया गया दोषी

प्रमिला मोडियम - मिलिट्री कंपनी नंबर-2 के कैडरों के साथ झीरम पहुंची और हमले में शामिल हुई। घायलों पर हमला करने और हथियार लूटने का भी आरोप।

चैतू लेकाम - PLGA का सेक्शन कमांडर। पिड़िया से झीरम पहुंचा और हमले में शामिल हुआ। FSL और अन्य सबूतों से बरामद विस्फोटकों का हमले से संबंध मिला।

सुमित्रा पुनेम मोडियम - अन्य कैडरों के साथ झीरम पहुंची और हमले में शामिल हुई।

मुक्का मंडावी - हथियार के साथ हमले में शामिल हुआ और पुलिसकर्मियों के हथियार लूटे। बरामद विस्फोटक घटनास्थल से मिले सामान से मेल खाए।

कवासी कोसा - झीरम हमले में शामिल हुआ और पुलिसकर्मियों के हथियार लूटे।

आयता मरकाम - कोलेंग और कंडानार से चावल व अन्य लॉजिस्टिक सामग्री जुटाई और उसे झीरम पहुंचाने की व्यवस्था की।

मड़कामी देवा - दरभा डिवीजन कमेटी का सदस्य। हमले के लिए लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराने में भूमिका निभाई।

जोगा मड़कम - झीरम हमले में शामिल हुआ और पुलिसकर्मियों के हथियार लूटे।

बंजामी सन्ना - दरभा डिवीजन कमेटी की सदस्य। हमले के लिए चावल और अन्य लॉजिस्टिक सामग्री जुटाई। फंड के लिए वसूली करने का भी आरोप।

महादेव नाग - धारा 164 CRPC के तहत दर्ज बयान में घटनास्थल पर मौजूदगी और हमले में उसकी भूमिका का उल्लेख।

NIA ने लीपापोती का काम किया- भूपेश

फैसले के बाद पूर्व CM भूपेश बघेल ने NIA पर लीपापोती का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बड़े नक्सली नेताओं और षड्यंत्र की जांच नहीं हुई, जबकि भाजपा षड्यंत्रकारियों को बचा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने पलटवार करते हुए कहा कि फैसला NIA की सशक्त जांच और न्यायपालिका की निष्पक्षता का नतीजा है। उन्होंने बघेल से पूछा- "जेब में कौन-सी पर्ची लेकर घूमते थे?" 25 मई 2013 के हमले में दिग्गज कांग्रेस नेताओं समेत 29 लोगों की मौत हुई थी, इनमें 10 पुलिसकर्मी थे और 38 लोग घायल हुए थे। आरोपियों के वकील अरविंद चौधरी ने कहा कि वे फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और हाईकोर्ट जाएंगे।

झीरम हमला राजनीतिक षड्यंत्र और सुपारी किलिंग थी- बैज

इस फैसले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बस्तर जानता है कि कांग्रेस नेताओं और जवानों की हत्या राजनीतिक षड्यंत्र और सुपारी किलिंग थी। सत्ता हासिल करने के लिए हत्याएं कराई गई थीं। जिन 10 लोगों को आरोपी बनाया गया, वे बड़े नक्सली नहीं थे। हमले की प्लानिंग करने वाले बड़े नक्सली लीडरों पर कार्रवाई नहीं हुई।

भाजपा के इशारे पर काम करती है एनआईएः तूलिका कर्मा

वहीं महेंद्र कर्मा की बेटी तूलिका कर्मा ने कहा कि अभी भाजपा की सरकार है। घटना के समय भी भाजपा की सरकार थी। एनआईए भी उन्हीं के इशारों पर चला। घटना के वक्त जो लोग मौजूद थे उन्हें ही पूछताछ के लिए बुलाया ही नहीं गया। न्याय के नाम पर खानापूर्ति कर दी गई। नंदकुमार पटेल के बेटे और विधायक उमेश पटेल ने कहा कि 10 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। षड्यंत्रों की जांच को लेकर मांग की गई थी। इसे लेकर आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

साजिश करने वाले खुलेआम घूम रहे- प्रत्यक्षदर्शी

झीरम हमले के प्रत्यक्षदर्शी और आरडीए के पूर्व उपाध्यक्ष शिव सिंह ठाकुर ने कहा कि झीरम के पीड़ितों के साथ न्याय नहीं हुआ है। हमले के पीछे कौन थे? उनका सच बाहर आना चाहिए। जिन्होंने साजिश की वो खुले आम घूम रहे हैं। बता दें कि शिव सिंह ठाकुर को हमले के दौरान पीठ पर गोली लगी थी।

सुखदेव भगत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रभारी बने

शहर सत्ता/रायपुर। सुखदेव भगत को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। विवादों के बाद भूपेश बघेल को पंजाब प्रभारी के पद से हटा दिया गया। उनकी जगह छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई। भूपेश बघेल को असम का महासचिव प्रभारी बनाया गया है। बता दें कि पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और उनके गुट ने बघेल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर दोबारा ताजपोशी के बाद से चन्नी गुट नाराज था।

चन्नी गुट के नेताओं के मुताबिक भूपेश बघेल ने प्रदेश प्रभारी होने के बावजूद कांग्रेस हाईकमान को पंजाब की असल ग्राउंड रियलिटी की जानकारी नहीं दी। चन्नी गुट बघेल और राजा वड़िंग को उनके पदों से हटाने पर अड़ा हुआ था। पूर्व सीएम चन्नी और उनके गुट के नेता तर्क दे रहे थे कि विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना है तो वड़िंग-बघेल को हटाकर इनकी जगह किसी अन्य मजबूत नेता को कमान सौंपी जाए। हाईकमान को आखिरकार चन्नी गुट के आगे झुकना पड़ा।

कांग्रेस हाईकमान ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रभारी सुखदेव भगत झारखंड के लोहरदगा से कांग्रेस सांसद हैं। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1960 को लोहरदगा में हुआ और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई की है। राजनीति में आने से पहले वे राज्य प्रशासनिक सेवा में कार्यरत थे। वर्ष 2005 में नौकरी छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़ा और लोहरदगा से विधायक चुने गए। मई 2013 में उन्हें झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। वे कई बार विधायक रहे। 2019 में वे भाजपा में शामिल हुए और विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जनवरी 2022 में कांग्रेस में वापसी कर ली।

सहायक ग्रेड-3 परीक्षा में रायपुर में 51% उपस्थिति, 64 पद भरे जाएंगे

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) की ओर से विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3 और प्रोसेस राइटर भर्ती परीक्षा 2026 रविवार को आयोजित की गई। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक हुई। प्रदेशभर में करीब 10,700 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत थे। इनमें लगभग 54% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। रायपुर में परीक्षा के लिए समन्वयक केंद्र-25, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय को केंद्र बनाया गया था। यहां कुल 18 परीक्षा केंद्रों पर 6032 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें 3083 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 2949 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। रायपुर के इन केंद्रों पर कुल उपस्थिति करीब 51.1% रही। रायपुर के परीक्षा केंद्रों में सबसे ज्यादा 205 अभ्यर्थी केंद्र क्रमांक 2503 पर उपस्थित हुए। इसके बाद केंद्र 2508 में 196, केंद्र 2510 में 198 और केंद्र 2514 में 194 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। वहीं केंद्र क्रमांक 2501 में 143 और केंद्र 2511 में 125 अभ्यर्थी उपस्थित रहे।

जातिगत जनगणना के फॉर्म पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

मौजूदा प्रश्नावली में ओबीसी का जिक्र तक नहीं, बदलाव की मांग

शहर सत्ता/रायपुर। नाना भाऊ पटोले ने प्रश्नावली के सवाल नंबर 10 पर सबसे ज्यादा आपत्ति जताई। कांग्रेस के मुताबिक, इसमें जाति का नाम लिखने के लिए ओपन-एंडेड विकल्प दिया गया है। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपनी जाति या उपजाति का जो नाम बताएगा, गणनाकर्मी उसे उसी रूप में दर्ज करेगा। कांग्रेस का कहना है कि देश के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में एक ही जाति को अलग-अलग नाम, बोली या स्पेलिंग से जाना जाता है। ऐसे में एक ही जाति के कई नाम दर्ज हो सकते हैं। इससे आंकड़ों में अंतर आने की आशंका है और जातियों की वास्तविक आबादी का सही अनुमान लगाना मुश्किल हो सकता है।

OBC की सही संख्या सामने नहीं आने की आशंका

कांग्रेस ने सवाल उठाया कि मौजूदा प्रश्नावली में 'पिछड़ा वर्ग' शब्द तक शामिल नहीं किया गया है। पटोले के मुताबिक, इसका सबसे ज्यादा असर ओबीसी, ईबीसी और अन्य वंचित वर्गों पर पड़ सकता है। अगर एक ही जाति के नाम अलग-अलग तरीके से दर्ज हुए तो उसकी वास्तविक संख्या कम या अलग-अलग हिस्सों में बंटी हुई दिखाई दे सकती है। कांग्रेस का कहना है कि इसका सीधा असर आरक्षण, सरकारी नौकरियों, शिक्षा, छात्रवृत्ति और कल्याणकारी योजनाओं में इन वर्गों की हिस्सेदारी तय करने पर पड़ सकता है।

कांग्रेस का सवाल- सूची मौजूद है तो इस्तेमाल क्यों नहीं?

नाना भाऊ पटोले ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास पहले से जातियों की सूचियां उपलब्ध हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना में इन्हें ड्रॉपडाउन सूची के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ओबीसी जातियों की सूची पहले से मौजूद है तो उसे जातिगत जनगणना की प्रश्नावली में शामिल क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस ने मांग की है कि जातिगत जनगणना की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और आम लोगों से चर्चा की जाए और उनके सुझावों के आधार पर नई प्रश्नावली तैयार की जाए।

2021 से जातिगत जनगणना की मांग कर रही कांग्रेस

पटोले ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग करती रही है। कांग्रेस के मुताबिक, यह मांग 2021 से लंबित थी और राहुल गांधी 2023 से लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जातिगत जनगणना को लेकर पत्र लिखा है। पार्टी का दावा है कि खरगे की ओर से 2023 और 2025 में भी इस संबंध में पत्र भेजे गए थे। कांग्रेस ने कहा कि 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने 2027 से जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की थी। अब पार्टी ने जनगणना की प्रश्नावली के प्रारूप पर सवाल उठाए हैं।

खारून-नदी में डूबे युवक का 30 घंटे बाद SDRF ने किया शव बरामद

रक्षाबंधन पर बहन की अस्थियां विसर्जित करने पहुंचा था

शहर सत्ता/रायपुर। राजधानी रायपुर में रक्षाबंधन के दिन खारुन नदी में डूबे युवक का शव करीब 30 घंटे बाद बरामद कर लिया गया है। युवक अपनी बहन की अस्थियां विसर्जित करने के लिए महादेव घाट पहुंचा था। इस दौरान वह नदी में डूब गया था। घटना के बाद से SDRF की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। मृतक की पहचान युधिष्ठिर सारंग के रूप में हुई है। रक्षाबंधन के दिन युवक परिवार के साथ बहन की अस्थियां लेकर खारुन नदी पहुंचा था। अस्थि विसर्जन के दौरान वह भंवर में फंसकर एनिकट के पास डूब गया था। घटना डीडी नगर थाना क्षेत्र के महादेव घाट की है। युवक के नदी में डूबने की सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की। टीम ने नदी के अलग-अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन चलाया। पानी की गहराई और तेज बहाव के कारण रेस्क्यू टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 30 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद SDRF की टीम ने युवक का शव नदी से बरामद कर लिया। शव मिलने के बाद मौके पर मौजूद परिजनों में मातम छा गया।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

बहन की अस्थियों का विसर्जन करने पहुंचे परिवार के लिए यह हादसा बेहद दर्दनाक रहा। जिस दिन परिवार बहन को अंतिम विदाई देने नदी पहुंचा था, उसी दिन भाई की भी मौत हो गई। घटना के बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद प्रशासन ने लोगों से नदी में उतरते समय सावधानी बरतने और गहरे पानी में जाने से बचने की अपील की है।

कारोबारी को धमकी...5 करोड़ दो,वरना जान से जाओगे

शहर सत्ता/रायपुर। तलाक की सुनवाई के बाद कारोबारी से 5 करोड़ रुपए मांगने और रकम नहीं देने पर हत्या की धमकी देने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता मुकेश संचेती ने पत्नी के भाइयों और जीजा पर धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित आरएस पुरम थाने में जीरो नंबरी FIR दर्ज की गई है। रायपुर पुलिस ने खम्हारडीह थाना में मामला दर्ज किया है। शिकायत के मुताबिक, मुकेश की शादी करीब 17 साल पहले सिया संचेती से हुई थी। दोनों के दो बच्चे हैं। बेटा 15 साल और बेटी 10 साल की है। दंपती के बीच तलाक का मामला रायपुर फैमिली कोर्ट में चल रहा है। मुकेश के मुताबिक, 27 अप्रैल 2026 को रायपुर फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका पर सुनवाई थी। आरोप है कि इस दौरान पत्नी ने 5 करोड़ रुपए और गुजारा भत्ते की मांग की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पत्नी के भाई अंकित गोल्छा ने नोटरीकृत हलफनामे पर हस्ताक्षर नहीं करने पर रायपुर से सुरक्षित नहीं जाने देने की धमकी दी। आरोप है कि अंकित ने उसकी हत्या कर शव के टुकड़े करने की धमकी भी दी। वहीं, शिकायत में साढ़ू भूरूमल कोटडिया पर भी गाली-गलौज करने और 5 करोड़ रुपए नहीं देने पर हत्या कर दफनाने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है।

पैसे नहीं देने पर चाकू मारने वाला आरोपी गिरफ्तार

शहर सत्ता/रायपुर। शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर युवक से गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने और चाकू से हमला करने वाले आरोपी अभय रक्सेल को आजाद चौक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक, अभय के खिलाफ हत्या के प्रयास के 3 मामलों समेत बलवा, आर्म्स एक्ट, लूट, मारपीट और अन्य गंभीर अपराधों के आधा दर्जन से ज्यादा मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक, अमन पटेल ने आजाद चौक थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 31 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 12 बजे वह आजाद चौक इलाके की एक चाय दुकान पर चाय पीने गया था। इसी दौरान एक युवक उसके पास आया और पता पूछने के बाद शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। अमन ने पैसे देने से मना किया तो आरोपी उसके साथ अश्लील गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने दोबारा शराब के लिए पैसे मांगे और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद अपने पास रखी नुकीली वस्तु से अमन पर हमला कर दिया। हमले में वह घायल हो गया। उसका उपचार एम्स अस्पताल में चल रहा है। शिकायत के आधार पर आजाद चौक पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी के खिलाफ जांच शुरू की थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी ने 5 जून 2026 को न्यायालय के समक्ष समर्पण किया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर जब्त किया गया।

बच्चों को धमकाकर घर से चोरी करवाते थे जेवर

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर के गुढ़ियारी इलाके में नाबालिग बच्चों को बहला-फुसलाकर अपने झांसे में लेने के बाद डराने-धमकाने और ब्लैकमेल कर सोने-चांदी के जेवर और नकदी की उगाही करने वाले पति-पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वंदना साहू और उसके पति दीपक साहू बच्चों को घर से चोरी करके जेवर और पैसे लाने के लिए मजबूर करते थे। मामले में 11 साल की बच्ची से उसकी नानी का रानीहार, सोने की चेन और कान के झुमके भी मंगवाए गए थे। शिकायत के बाद गुढ़ियारी पुलिस ने जांच कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से सोने के कान के टॉप्स और चेन बरामद की है। पुलिस के मुताबिक, गुढ़ियारी निवासी सोनम साहू ने 4 सितंबर को थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी 11 वर्षीय भांजी के पास घर में रखे सोने के झुमके और चेन थे। आरोप है कि वंदना साहू ने बच्ची को डराया-धमकाया और दबाव बनाकर ये आभूषण अपने पास मंगवा लिए। शिकायत के अनुसार, 2 सितंबर को भी बच्ची पर उसकी नानी पार्वती साहू का रानी हार लाने के लिए दबाव बनाया गया। आरोप है कि महिला के कहने पर बच्ची ने घर से रानी हार निकाल लिया और उसे देने जा रही थी। इसी दौरान परिवार को इसकी जानकारी हो गई, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया।

11 सितंबर को सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन

86 महीने के एरियर और नियमितीकरण की मांग

शहर सत्ता/रायपुर। रायपुर। महंगाई भत्ते, एरियर और नियमितीकरण समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के नियमित-अनियमित कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर्स अब आंदोलन की तैयारी में हैं। 'एक मांग-एक मंच अभियान' के बैनर तले 11 सितंबर को इंद्रावती भवन के सामने भोजनावकाश में सांकेतिक प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। संगठन का आरोप है कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार और प्रशासन गंभीर नहीं हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से कई मांगें लंबित हैं, जिससे कर्मचारियों के आर्थिक हित प्रभावित हो रहे हैं। कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांग है कि जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता जारी किया जाए और 86 महीने का एरियर दिया जाए। संगठनों का कहना है कि न्यूनतम वेतन में पिछले 9 साल से और संविदा वेतन में पिछले 3 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इससे बड़ी संख्या में अनियमित कर्मचारियों पर आर्थिक असर पड़ रहा है।

नियमितीकरण से लेकर आउटसोर्सिंग बंद करने की मांग

कर्मचारी संगठनों ने अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण और निकाले गए कर्मचारियों की बहाली की मांग की है। इसके अलावा न्यून मानदेय वाले कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने और आउटसोर्सिंग व ठेका व्यवस्था से कर्मचारियों की नियुक्ति बंद करने की मांग भी रखी गई है।

50 से ज्यादा संगठनों का समर्थन

आयोजकों के मुताबिक प्रदर्शन को 50 से ज्यादा कर्मचारी संगठनों का समर्थन मिला है। इंद्रावती भवन और नवा रायपुर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। पेंशनर, स्वास्थ्य कर्मचारी, महिला एवं बाल विकास विभाग और वन विभाग के कर्मचारी संगठनों समेत कई संगठनों ने प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है।

ये हैं कर्मचारियों की 5 प्रमुख मांगें

- जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता और 86 महीने का एरियर दिया जाए।
- अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली और न्यूनतम वेतन दिया जाए। आउटसोर्सिंग/ठेका व्यवस्था बंद की जाए।
- नगरीय निकाय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।
- स्वास्थ्य विभाग में लैब और फार्मेसी की ठेका पद्धति खत्म की जाए।
- नियमित-अनियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए मध्यप्रदेश की तर्ज पर 20 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा लागू की जाए।

तीजा तिहार पर तोहफा, बेलतरा महोत्सव के लिए 30 लाख की सौगात

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्व तीजा तिहार के अवसर पर रविवार को बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में भव्य तीजा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आयोजन स्थल पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपरा की खास झलक देखने को मिली। बड़ी संख्या में माताएं-बहनें पारंपरिक वेशभूषा में कार्यक्रम में पहुंचीं। बच्चों ने भी विभिन्न गतिविधियों में उत्साह के साथ हिस्सा लिया। पूरे स्टेडियम में तीजा पर्व को लेकर उत्साह और उमंग का माहौल रहा। महिलाओं के लिए झूले, मेहंदी और मनोरंजन से जुड़ी कई गतिविधियां आयोजित की गईं। वहीं, माताओं-बहनों के लिए भोजन और उपहार की भी व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीजा पर्व को छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व बताया। उन्होंने कहा कि तीजा माताओं और बहनों की आस्था, प्रेम और पारिवारिक समर्पण का पर्व है। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना के लिए श्रद्धापूर्वक व्रत रखती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सनातन परंपरा में महिलाओं को हमेशा सम्मान का स्थान दिया गया है। उन्होंने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों का भी जिक्र किया। CM साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की 68 लाख से अधिक माताओं-बहनों को अब तक 31 किश्तों की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

छत्तीसगढ़ में 97 हजार से अधिक निरक्षर, बिलासपुर में सर्वाधिक

शहर सत्ता/रायपुर। राज्य में शत-प्रतिशत नामांकन और 'स्कूल चलो अभियान' जैसे प्रयासों के बावजूद निरक्षरों के ताजा आंकड़े चिंताजनक हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी 33 जिलों में कराए गए सर्वे में 97,679 निरक्षरों की पहचान की गई है। इनमें सर्वाधिक 11,328 निरक्षर बिलासपुर जिले में मिले हैं, जो बस्तर (7,997) और सरगुजा (3,568) जैसे आदिवासी बहुल जिलों की तुलना में भी अधिक हैं। 'उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' के तहत यह सर्वे 20 मई से 27 अगस्त तक चला। जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण के अनुसार, बिलासपुर के कुल 11,328 निरक्षरों में से 10,908 ग्रामीण क्षेत्रों में और 420 नगरीय निकायों के 163 वार्डों में मिले हैं। अब चिह्नित लोगों को अक्षर और अंक ज्ञान के साथ बुनियादी संख्यात्मक कौशल सिखाया जाएगा। इसके बाद सितंबर के अंत में होने वाली महापरीक्षा में शामिल कराया जाएगा। कलेक्टर ने अभियान को गति देने के लिए अधिकारियों को साक्षरता पखवाड़ा चलाने के निर्देश दिए हैं।

10 निरक्षरों को पढ़ाकर पास कराया तो छात्रों को 10 बोनस अंक अभियान में स्कूली विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए शासन ने नई पहल की है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो विद्यार्थी 10 निरक्षरों को पढ़ाकर महापरीक्षा में उत्तीर्ण कराएंगे, उन्हें स्थानीय या बोर्ड परीक्षा में 10 बोनस अंक दिए जाएंगे। पारा-मोहल्लों में पांच से 10 शिक्षार्थियों के लिए स्थानीय स्कूलों को साक्षरता केंद्र बनाया गया है। सभी शिक्षार्थियों और स्वयंसेवी शिक्षकों का 15 सितंबर तक 'उल्लास' मोबाइल एप पर डिजिटल पंजीयन किया जाएगा।

रायपुर के 10 जोन में लगेंगे 160 हाईटेक कैमरे

शहर सत्ता/रायपुर। शहर की सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने वालों पर अब नगर निगम की नजर रहेगी। रायपुर के सभी 10 जोन में इस महीने करीब 160 हाईटेक नाइट विजन कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों की मदद से सड़क किनारे कचरा फेंकने, वाहन से कचरा उतारने या खुले में कचरा डालने वालों की पहचान की जाएगी। निगम के मुताबिक कैमरों की रिकॉर्डिंग के आधार पर संबंधित व्यक्ति या वाहन तक पहुंचकर कार्रवाई की जाएगी। कैमरों को सोलर पैनल और माइक्रोचिप सिस्टम से संचालित किया जाएगा, जिससे बिजली की नियमित सप्लाई पर निर्भरता कम होगी।

अंधेरे में भी 50 मीटर तक रिकॉर्डिंग

कैमरों में नाइट विजन की सुविधा होगी। अंधेरे में भी करीब 50 मीटर तक की तस्वीर साफ रिकॉर्ड की जा सकेगी। जरूरत पड़ने पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में इसकी निगरानी क्षमता और बढ़ जाएगी। निगम अधिकारियों के अनुसार कैमरों की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाएगा। किसी जगह कचरा फेंकने की घटना सामने आने पर फुटेज के जरिए व्यक्ति या वाहन की पहचान कर कार्रवाई की जा सकेगी। सिर्फ सड़क पर कचरा फेंकने वालों की ही नहीं, बल्कि कचरा कलेक्शन के लिए चलने वाले वाहनों की भी निगरानी की जाएगी। वाहनों के नंबर रिकॉर्ड किए जाएंगे और यह पता लगाया जा सकेगा कि कचरा कहां से उठाया गया और उसे किस जगह डाला गया।

मोबाइल ऐप से 24 घंटे मॉनिटरिंग

कैमरों की निगरानी के लिए मोबाइल ऐप से जुड़ा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसमें जोन कमिश्नर और संबंधित अधिकारी-कर्मचारी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग कर सकेंगे।

बाल विवाह रोकने भारत की मुहिम को UN की मंजूरी

छत्तीसगढ़ में 3 साल में 8,414 मामले रोके

शहर सत्ता/रायपुर। बाल विवाह के खिलाफ छत्तीसगढ़ में चल रही मुहिम को अब अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। संयुक्त राष्ट्र ने 27 नवंबर को 'बाल विवाह, कम उम्र और जबरन विवाह के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस' घोषित किया है। इसी दिन 2024 में भारत सरकार ने 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान शुरू किया था। छत्तीसगढ़ में इस अभियान के तहत पिछले तीन साल में 8,414 बाल विवाह रुकवाने का दावा किया गया है। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) के मुताबिक, राज्य के सभी 33 जिलों में आठ सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर बाल विवाह रोकने के लिए काम किया जा रहा है। संगठन की ओर से समुदायों, स्कूलों, पंचायतों, पुलिस, धर्मगुरुओं और जनप्रतिनिधियों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है।

छत्तीसगढ़ में 18 साल से पहले शादी का आंकड़ा घटा

आंकड़ों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में 18 साल से पहले शादी करने वाली लड़कियों का आंकड़ा भी कम हुआ है। एनएफएचएस-5 (2019-21) में यह 12.1 प्रतिशत था, जो एनएफएचएस-6 (2023-24) में घटकर 10.1 प्रतिशत हो गया। हालांकि, देश का आंकड़ा 20.1 प्रतिशत है। भारत ने 2026 तक बाल विवाह की दर को 10 प्रतिशत और 2030 तक इसे पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है।

भारत की पहल को UN की मंजूरी

जेआरसी के संस्थापक भुवन ऋभु ने बाल विवाह के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित करने की पहल की थी। मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र के सामने यह प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद सिएरा लियोन ने भारत समेत 67 देशों के समर्थन से प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किया, जिसे 4 सितंबर को मंजूरी मिल गई। जेआरसी के मुताबिक, देशभर में पिछले तीन साल में 5.50 लाख से ज्यादा बाल विवाह रुकवाने का दावा किया गया है। संगठन फिलहाल देश के 782 जिलों में बाल विवाह के खिलाफ अभियान चला रहा है।

25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ली थी शपथ

भुवन ऋभु के मुताबिक, 27 नवंबर 2024 को देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली थी। उनका कहना है कि भारत का यह अभियान अब 99 से ज्यादा देशों तक पहुंच चुका है। दिसंबर 2024 में नेपाल में भी 'बाल विवाह मुक्त नेपाल' अभियान शुरू किया गया था। जेआरसी ने दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक 100 दिन का अभियान भी चलाया था। इसके तहत 100 देशों और एक लाख स्कूलों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था।

रायपुर में डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपी गिरफ्तार

कचना इलाके की ज्वेलर्स शॉप में थी वारदात की तैयारी

शहर सत्ता/रायपुर। ज्वेलर्स शॉप को निशाना बनाने से पहले ही पुलिस ने डकैती की योजना को नाकाम कर दिया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान खम्हारडीह के महेश धीवर, नितिन उर्फ सोनू बैस, खेमलाल सेन, लक्ष्मण साहू और पीयूष कुमार साहू के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी कचना इलाके के आसपास किसी ज्वेलर्स शॉप में डकैती डालने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से धारदार हथियार, 4 मोबाइल फोन और 2 वाहन बरामद किए हैं। मामला खम्हारडीह थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक, 6 सितंबर को सूचना मिली थी कि खम्हारडीह इलाके के एक खेल मैदान में कुछ युवक दोपहिया और चारपहिया वाहनों के साथ बैठे हैं। उनके पास धारदार हथियार हैं और वे लूट या डकैती की वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही मैदान में बैठे युवक भागने लगे।

पूछताछ में योजना कबूली

पूछताछ में आरोपियों ने डकैती की योजना बनाने की बात कबूल की है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों और उनके वाहनों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को 2 बटनदार चाकू, एक बड़ा स्टील चाकू, 2 कैंची और एक स्टील पाइप मिला। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। इसके अलावा एक होंडा बाइक (CG 04 QT 4258) और टाटा एस डीआई वाहन (CG 04 JD 9030) भी कब्जे में लिया गया है। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने कचना क्षेत्र के आसपास स्थित ज्वेलर्स शॉप में डकैती करने की योजना बनाना स्वीकार किया। पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार कर खम्हारडीह थाने में अपराध क्रमांक 348/26 के तहत धारा 310(4) बीएनएस और 25 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है।

संपादकीय

सुकांत राजपूत

विकास के आंकड़ों के बीच जेब क्यों हो रही ढीली

देश में बढ़ती महंगाई आज आम आदमी के जीवन से जुड़ी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि से न केवल लोगों की क्रयशक्ति कम हो रही है, बल्कि सीमित आय में खर्च बढ़ने से घरेलू बजट का संतुलन भी बिगड़ रहा है। यह विचित्र बात है कि एक तरफ सरकार की ओर से विकास दर के चमचमाते आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम लोगों की जेब ढीली होती जा रही है।

पहले चीनी महंगी हुई, फिर सीएनजी के दाम बढ़े और अब व्यावसायिक रसोई गैस सिलेंडर के दाम में साढ़े नौ रुपए तथा विमान ईंधन की कीमतों में 5.46 फीसद की बढ़ोतरी की गई। जाहिर है कि इससे भोजन की थाली और हवाई यात्रा का महंगा होना तय है। सवाल है कि जब आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर महंगाई को नियंत्रण में रखने के सरकार के दावों का क्या मतलब रह जाता है? क्या सरकार ने बाजार को पूरी तरह खुला छोड़ दिया है, ताकि वह मनमाने तरीके से कीमतें तय कर सके!

त्योहारों से पहले खुदरा महंगाई जिस तरह बढ़ी है, वह वास्तव में चिंता का विषय है। पिछले दिनों चीनी और प्याज के दाम बढ़ने का असर हर वर्ग पर पड़ा है। रसोई में इस्तेमाल होने वाली हर चीज अब महंगी हो चुकी है। वहीं, सरकारी आंकड़ों में कहा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में अनुमान से कहीं अधिक वृद्धि हुई है। इसके लिए सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन सवाल है कि इस वृद्धि को दर्ज करते समय महंगाई के आंकड़ों पर गौर क्यों नहीं किया गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हाल में सीएनजी के दाम तीन रुपए नवासी पैसे बढ़ाए गए थे, जबकि मुंबई में दो रुपए बढ़ाए गए हैं। साफ है कि आम लोगों को अब ऑटो-टैक्सी का अधिक किराया देना पड़ सकता है। कुछ समय पूर्व दिल्ली में दूध के दाम बढ़े थे, अब मुंबई में इसकी कीमतें बढ़ाई गई हैं। सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आर्थिक प्रगति का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब वस्तुओं की कीमतों को भी नियंत्रण में रखा जाएगा।

मकानों में कारोबार, गली-मोहल्लों में बाजार निगम के नियम तार-तार, आंखें खोलो सरकार...!

रोड डिवाइडर का जन्म ट्रैफिक को अनुशासन सिखाने के लिए हुआ था। उसका काम था—सड़क के बीच खड़े होकर दो दिशाओं से आने वाली गाड़ियों को अलग रखना, दुर्घटनाएं रोकना और यातायात को सुरक्षित बनाना। लेकिन हमारे शहर में भी डिवाइडर का काम कुछ और ही हो गया है। वह ट्रैफिक को नहीं, बधाई संदेशों को सुरक्षित रखने का काम कर रहा है और बधाई भी ऐसी कि जिसे देखकर लगता है कि शहर की सबसे बड़ी समस्या यातायात नहीं, शुभकामनाओं की कमी है।

किसी का जन्मदिन हो—डिवाइडर पर बधाई।

किसी की नियुक्ति हो—डिवाइडर पर बधाई।

किसी को नया पद मिला हो—डिवाइडर पर बधाई।

किसी का स्वागत करना हो—डिवाइडर पर बधाई।

और किसी को अपनी सार्वजनिक मौजूदगी दर्ज करानी हो, तो डिवाइडर सबसे सस्ता और सबसे बड़ा विज्ञापन बोर्ड है।

डिवाइडर अब सड़क का नहीं, सार्वजनिक पहचान का सहारा है। विडंबना देखिए, जिस डिवाइडर पर कभी पौधे लगने चाहिए थे, वहां अब मुस्कुराते हुए चेहरे उग आए हैं। हर कुछ दूरी पर एक नया चेहरा—शहर में विकास कम और बधाई देने वाले ज्यादा पैदा हो रहे हैं। जन्मदिन साल में एक बार आता है, लेकिन शुभचिंतकों की बधाई देखकर लगता है कि जन्मदिन रोज है। डिवाइडर पर संदेशा लगाने के लिए क्या नगर निगम की अनुमति ली जाती है ? यह सवाल पूछना ही शायद व्यवस्था को असहज कर देता है। कहीं-कहीं तो उन्हीं नगर निगम के महानुभावों को बधाई देते हुए होर्डिंग लगे दिखाई देते हैं, जिनकी जिम्मेदारी सार्वजनिक जगहों पर अवैध होर्डिंग और अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की है। अब इसे संयोग कहें या व्यवस्था का नया संस्करण! जिसे निगरानी करनी है, उसी के सम्मान में निगरानी वाली जगह पर होर्डिंग लगा दिया गया।

फिर कार्रवाई कौन करेगा?

सड़क जनता के टैक्स से बनती है। डिवाइडर जनता के पैसे से बनता है। उसकी सफाई और रखरखाव पर सरकारी पैसा खर्च होता है। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को निजी प्रचार की दीवार समझने वालों की कमी नहीं है। आजकल बधाई के होर्डिंग्स में चेहरा इतना बड़ा रहता है कि पीछे सड़क छोटी दिखाई देती है। नाम इतना बड़ा कि पद पढ़ने के लिए चश्मा नहीं, दूरबीन चाहिए और नीचे बधाई देने वालों की ऐसी लंबी सूची कि देखकर लगता है कि पूरा शहर शुभकामनाओं की कतार में खड़ा है। असल में यह बधाई कम और सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराने की होड़ ज्यादा है।

कभी शहर में पेड़ लगाए जाते थे। अब होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। कभी डिवाइडर हरियाली से सुंदर होते थे। अब उन पर मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। कभी सार्वजनिक जगहें शहर की सुंदरता बढ़ाती थीं। अब वे सार्वजनिक प्रचार का माध्यम बन गई हैं और जनता? जनता उसी सड़क पर हॉर्न बजाती हुई निकल रही है, जिसके बीचों-बीच उसे रोज किसी न किसी चेहरे को बधाई देनी पड़ती है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर नगर निगम की अनुमति के बिना डिवाइडर पर होर्डिंग्स लगाना गलत है, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती ? अगर गलत नहीं है, तो फिर अनुमति की व्यवस्था किसलिए है ? अगर सार्वजनिक संपत्ति पर कोई भी प्रचार संदेश लगाया जा सकता है, तो फिर उसे सार्वजनिक संपत्ति कहने का औचित्य क्या है ? और अगर नियम सबके लिए बराबर हैं, तो फिर डिवाइडर पर चमकते चेहरे देखकर नियम अपना चश्मा क्यों उतार लेते हैं ? यह सिर्फ होर्डिंग्स का मामला नहीं है। यह उस मानसिकता का मामला है जिसमें सार्वजनिक जगह को निजी प्रचार की जगह समझ लिया गया है और प्रशासन को मूक दर्शक।

कॉलम - खुरचन

द्वारा- हरिदास

डिवाइडर को ट्रैफिक का प्रहरी होना था, लेकिन हमने उसे प्रचार का पोस्टर-बॉय बना दिया। कल को शायद एंबुलेंस भी डिवाइडर से रास्ता मांगती मिलेगी और फ्लेक्स मुस्कुराकर कहेगा—"पहले बधाई पढ़ लो, रास्ता बाद में मिलेगा।" यही हमारे शहर की सबसे बड़ी विडंबना है—सड़क पर गाड़ियां अपनी दिशा खोज रही हैं और डिवाइडर पर प्रचार अपना रास्ता।

नगर निगम की नजर बड़ी तेज है। सड़क किनारे गरीब का ठेला दिख जाता है। फुटपाथ पर सब्जी बेचता आदमी दिख जाता है। चाय की गुमटी दिख जाती है। फल का ठेला दिख जाता है। बस, नगर निगम की गाड़ी आती है और फरमान सुनाती है—"हटाओ, अतिक्रमण है!"

बेचारा ठेले वाला हाथ जोड़ता है—"साहब, यहीं से घर चलता है।"

जवाब आता है—"नियम सबके लिए बराबर हैं।"

गरीब अपना ठेला समेट लेता है। उसकी शाम की कमाई सड़क पर बिखर जाती है और वह अगले दिन फिर किसी कोने की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन उसी सड़क के डिवाइडर पर अगर विशाल होर्डिंग टंगा हो तो नगर निगम की नजर अचानक कमजोर पड़ जाती है। गरीब का अस्थायी कारोबार अतिक्रमण दिखाई देता है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति पर महीनों से टंगा स्थायी प्रचार शायद व्यवस्था की नजर में सिर्फ "सजावट" है।

अगर सड़क और सार्वजनिक जगह अतिक्रमण मुक्त रखनी है, तो नियम डिवाइडर से भी शुरू होना चाहिए। जिस हाथ में गरीब का ठेला हटाने की ताकत है, उसी हाथ में अवैध होर्डिंग उतारने का साहस भी होना चाहिए। क्योंकि अतिक्रमण तो अतिक्रमण है—चाहे वह किसी गरीब के ठेले का हो या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के होर्डिंग का। वरना शहर में यही संदेश जाएगा कि नियम कमजोर के लिए लोहे की छड़ है और रसूखदार के लिए रबर की रस्सी।

अनुसंधान प्रयोगशालाओं से 'विकसित भारत' की कक्षाओं तक

डॉ. सुकांत मजूमदार

लेखक केंद्रीय शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री हैं

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार केवल व्यक्तिगत उत्कृष्टता की पहचान नहीं हैं; ये हमारे देश के भविष्य को आकार देने वाले प्रमुख शिल्पकारों का सम्मान करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज़न के मार्गदर्शन में तथा 'विकसित भारत 2047' की दिशा में भारत की सामूहिक यात्रा में, नवाचार को अक्सर वैश्विक सूचकांक और वित्तीय खर्च जैसे तकनीकी नजरिए से देखा जाता है। फिर भी, नवाचार मूल रूप से एक मानवीय प्रयास है — यह छात्र की आँखों में जिज्ञासा की चमक और उस शिक्षक का अटूट समर्पण है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा पीछे न छूट जाए।

भारत में शिक्षा के मौजूदा विकास की सबसे खास बात यह है कि उच्च-स्तरीय प्रयोगशाला अनुसंधान और कक्षा की रोज़मर्रा की हकीकत के बीच सोच-समझकर एक पुल बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत, नवाचार की परिकल्पना सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले एक उत्प्रेरक के तौर पर की गयी है। यह विज़न इस बात पर ज़ोर देता है कि देश की वास्तविक प्रगति तभी हो सकती है, जब हमारे सबसे बेहतरीन शोध का फ़ायदा आखिरी कतार में बैठे आखिरी बच्चे तक पहुँचे।

इस बड़े बदलाव के पैमाने को समझने के लिए, सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान इकोसिस्टम में व्यापक स्तर पर हो रहे महत्वपूर्ण बदलावों को देखना होगा।

इक्कीसवीं सदी में अपनी संप्रभुता और आर्थिक नेतृत्व को मज़बूत करने की कोशिश कर रहे देश के लिए, एक मज़बूत अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) इकोसिस्टम बहुत जरूरी है। भारत में एक मौलिक बदलाव आया है; देश अब मुख्य रूप से वैश्विक तकनीक को अपनाने के बजाय, वैश्विक चुनौतियों के लिए समाधान विकसित करने की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। यह बदलाव वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की बढ़ती रैंकिंग में प्रतिबिंबित होता है, जहाँ देश 2014 के 76वें स्थान से ऊपर उठकर 2025 में 38वें स्थान पर पहुँच गया है।

हालाँकि, असली कहानी भारत की कार्यक्षमता में छिपी है। नवाचार इनपुट के 52वें स्थान की तुलना में, भारत नवाचार आउटपुट में अब दुनिया भर में 32वें स्थान पर है। यह दिखाता है कि देश में नवाचार इनपुट को बड़े प्रभाव वाले नतीजों में बदलने की क्षमता, कई दूसरे देशों के मुक़ाबले ज़्यादा बेहतर है। इस संस्कृति को 6,000 से ज़्यादा उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में आर एंड डी प्रकोष्ठ बनाकर और 59,300 अनुसंधान सहयोग स्थापित करके संस्थागत रूप दिया गया है।

प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप (पीएमआरएफ) द्वारा समर्थित भारत का प्रतिभा समूह भी अनुसंधान इकोसिस्टम के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा है। पीएमआरएफ ने 3,688 विद्वानों का समर्थन किया है, जिसके परिणामस्वरूप 10,300 शैक्षिक पत्रिका प्रकाशन, 7,966 सम्मेलन पत्र, 834 पेटेंट दाखिले और 221 पेटेंट स्वीकृत हुए हैं। पीएमआरएफ 2.0 10,000 फ़ेलोशिप का समर्थन करने के लिए तैयार है, और प्रधानमंत्री अनुसंधान प्रभाग (पीएमआरसी) को पहले ही 3,600 से अधिक फ़ेलोशिप आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, इस प्रकार भारत की बौद्धिक अवसंरचना का विस्तार जारी है। इसे उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) ने और बढ़ावा दिया है, जिसने 111 संस्थानों में 281 परियोजनाओं के लिए ₹47,000 करोड़ से अधिक की मंजूरी दी है।

"भारत में एआई निर्माण" के विज़न को आगे बढ़ाने के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में चार समर्पित उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें ₹1,490 करोड़ का संचयी निवेश किया जाएगा:

* स्वास्थ्य सेवा: आईआईएससी बेंगलुरु
* स्थायी शहर: आईआईटी कानपुर
* कृषि: आईआईटी रोपड़
* शिक्षा: आईआईटी मद्रास

जहां यह अवसंरचना भारत की प्रगति का आधार प्रदान करती है, वहीं ज्ञान का लोकतंत्रीकरण इसे जीवंत बनाता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि दूर-दराज़ के गाँव का कोई महत्वाकांक्षी शोधार्थी भी बड़े शहर के शोधार्थी जितने ही मौकों का फ़ायदा उठा सके, भारत ने अतीत में ज्ञान तक सीमित पहुँच वाली व्यवस्थाओं को खत्म करने की कोशिश की है। 'एक राष्ट्र, एक सदस्यता' (ओएनओएस) पहल शैक्षिक समानता के लिए एक अहम साधन है, जो 1.8 करोड़ छात्रों और संकाय सदस्यों को 13,000 अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक पत्रिकाओं तक पहुँच प्रदान करती है।

इसकी रफ़्तार भी उतनी ही अहम है। 2025 के 11.4 करोड़ संपूर्ण-पाठ डाउनलोड के बाद, 2026 के शुरुआती छह महीनों में ही 6.26 करोड़ लेखों तक पहुँचा गया है। यह ज्ञान के प्रति उत्सुक देश की नब्ज को दर्शाता है।

ज्ञान तक पहुँच का यह विस्तार भारत के बौद्धिक संपदा इकोसिस्टम में आए बड़े बदलाव के साथ-साथ हुआ है। घरेलू पेटेंट दाखिला 2014–15 के 42,763 से बढ़कर 2024–25 में 1,10,375 हो गया है, जो 158% की भारी वृद्धि को रेखांकित करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2021–22 के बाद से इन दाखिलों में शिक्षा क्षेत्र की हिस्सेदारी तीन गुना बढ़ गई है, जो 11.15 प्रतिशत से बढ़कर 34.13 प्रतिशत हो गई है। कपिला कार्यक्रम जैसी पहल, जिसने 13,067 पेटेंट दाखिले में मदद की है, और 418 संस्थानों में आईडिया लैब नेटवर्क, आविष्कारकों की अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने में मदद कर रहे हैं।

यह भारत की बढ़ती बौद्धिक संप्रभुता का परिणाम है। उच्च शिक्षा संस्थान अब केवल सीखने की जगहें नहीं रह गए हैं; वे तेज़ी से नवाचार-आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था के इंजन बन रहे हैं। भारत के लगभग 125 यूनिकॉर्न में से 86 उच्च शिक्षा संस्थानों से निकले हैं, जिनमें से 62 खास तौर पर आईएआईटी और आईएआईएससी से जुड़े हैं।

फिर भी, समावेश के बिना नवाचार केवल तकनीकी प्रगति है; सहानुभूति के साथ नवाचार एक सभ्यतागत विजय है। इस विजय का सबसे महत्वपूर्ण स्थान समावेशी कक्षा है।

छोटी सी शुरुआत

एक छोटे से गाँव में रवि नाम का लड़का रहता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह पढ़-लिखकर अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहता था। रोज सुबह वह अखबार बाँटता और उसके बाद स्कूल जाता। कई लोग उसका मज़ाक उड़ाते और कहते, "तुम जैसे गरीब लड़के बड़े सपने मत देखा करो।" रवि चुप रहता और मेहनत करता रहता। एक दिन परीक्षा में वह पूरे जिले में प्रथम आया। उसे छात्रवृत्ति मिली और आगे की पढ़ाई का रास्ता खुल गया। वर्षों की मेहनत के बाद वह एक सफल अधिकारी बना। गाँव लौटकर उसने सबसे पहले उन बच्चों के लिए पुस्तकालय बनवाया, जिनके पास पढ़ने के साधन नहीं थे। रवि ने कहा, "परिस्थितियाँ हमारे सपनों को छोटा नहीं करतीं, हमारी हिम्मत उन्हें छोटा करती है। अगर शुरुआत छोटी हो, तो भी कदम रुकने नहीं चाहिए।" सीख: सफलता के लिए साधन नहीं, निरंतर मेहनत और विश्वास जरूरी है।

'होर्मुज' से फिर दौड़ने लगा तेल, सप्लाई चैन हुआ नार्मल

नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एनर्जी की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है. इस बीच यूएस प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल टूथ पर पोस्ट कर दावा किया कि होर्मुज से तेल की आवाजाही अब फिर से सामान्य हो गई है. उन्होंने कहा कि जंग से पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल, कंडेनसेट और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की आवाजाही होती थी. ईरान के साथ फिर से बनी जंग की स्थिति के बीच ट्रंप ने कहा कि अब इस रास्ते से 1.8 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है. ट्रंप का ये पोस्ट ऐसे समय में आया है जब वह लगातार ईरान पर हमला करने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का नाम बदलने की धमकी दे रहे हैं. ट्रंप ने कहा कि चूंकि होर्मजु अब अमेरिका के नियंत्रण में है तो इसका नाम 'ट्रंप स्ट्रेट' रखा जाना चाहिए. ओमान की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है. इस क्षेत्र में किसी भी तरह के सैन्य या राजनीतिक तनाव का असर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है.

सहारनपुर मस्जिद विवाद पर ओवैसी का बड़ा दावा

जयपुर। जयपुर में सहारनपुर मस्जिद विवाद को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने मस्जिद गिराए जाने की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों के मामले में कानून और संविधान के प्रावधानों का पालन होना चाहिए. ओवैसी ने यह भी दावा किया कि जिस जगह मस्जिद बनी थी, वहां एक स्थानीय मुस्लिम परिवार ने मस्जिद के साथ मंदिर के लिए भी जमीन दी थी. ओवैसी के मुताबिक, सहारनपुर की विवादित मस्जिद कोई नई बनी हुई इमारत नहीं थी. उनका कहना है कि मस्जिद के निर्माण के समय स्थानीय मुस्लिम परिवार ने धार्मिक इस्तेमाल के लिए जमीन उपलब्ध कराई थी. उन्होंने दावा किया कि मस्जिद वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है और उसे कानूनी संरक्षण प्राप्त था. हालांकि, प्रशासन का पक्ष इससे अलग है. अधिकारियों के अनुसार सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद सरकारी जमीन पर स्थित थी और इसे अनधिकृत माना गया था. जुलाई में सिटी मजिस्ट्रेट ने इसे खाली कराने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ मस्जिद प्रबंधन की अपील 2 सितंबर को खारिज हो गई. इसके बाद 5 सितंबर को मस्जिद को गिरा दिया गया.

मरियम नवाज ने खोली पाक सेना की पोल

नई दिल्ली। पाकिस्तानी सेना अपने देश में होने वाले हर एक आतंकी हमले का झूठा इल्ज़ाम हमेशा भारत और अफगानिस्तान पर लगाती है लेकिन आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री एवं नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने लाहौर में एआई हब की लांचिंग के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को ख़तरा पड़ोसी देश (भारत) से कम और पाकिस्तान के ही पंजाब प्रांत के पड़ोसी प्रांत (खैबर पख्तूनख्वाह और बलूचिस्तान) से ज्यादा है, जहां से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आतंकवाद अता है. पंजाब प्रांत में आतंकवाद और क्राइम को कम करने के लिये Provincial Intelligence Fusion and Threat Assessment Center (PIFTAC) और Artificial Intelligence (AI) Hub की लांचिंग के समय मरयम नवाज ने दावा किया कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में क्राइम 70% तक कम हुआ है।

दिल्ली में 5 मंजिला हॉस्टल गिरा, 1 की मौत

तीन गंभीर रूप से घायल, दावा– बेसमेंट में खुदाई जारी थी

नई दिल्ली। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को एक 5 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। इसमें एक स्टूडेंट की मौत हो गई। वहीं, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। बिल्डिंग में हॉस्टल चलता था। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के वक्त छात्र कमरों में थे और बेसमेंट में खुदाई चल रही थी। 5 का रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि अभी यह पता नहीं चला है कि मलबे में कितने बच्चे फंसे हैं।

घटना दोपहर 1:30 बजे की है। स्थानीय लोग हथौड़े से मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मलबे में कुछ गाड़ियां भी दब गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मलबे के बगल में एक और बिल्डिंग गिरने की हालत में है। लेकिन लोगों को वहां से निकाल लिया गया है। सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहां बड़ी संख्या में छात्र PG और हॉस्टल में रहते हैं। इलाके में कई छात्र आवास हैं और आसपास वेंकटेश्वर कॉलेज, आर्यभट्ट कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज और मैत्रेयी कॉलेज जैसे संस्थान हैं। इसी वजह से यहां दिनभर छात्रों की आवाजाही रहती है। हालांकि, सत्य निकेतन में कुल कितने छात्र रहते हैं, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। सीएम रेखा गुप्ता ने बिल्डिंग गिरने की घटना पर दुख जाहिर किया है. उन्होंने कहा, "आर.के. पुरम के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना से बहुत चिंता है. DDMA, NDRF, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, MCD, CATS और सिविल डिफेंस की टीमें युद्ध स्तर पर बचाव कार्य कर रही हैं।

दिल्ली हादसा: एक्शन में अमित शाह, रद्द किया गोवा कार्यक्रम

दिल्ली के सत्य निकेतन में हुई इमारत गिरने की घटना पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दुख जताते हुए, अपना गोवा का कार्यक्रम रद्द कर दिया है. उन्हें आज गोवा के चिम्बेल में बीजेपी के नए बने राज्य कार्यलय भवन का उद्घाटन करना था. इस हादसे में अबतक एक शख्स की मौत हो चुकी है. वहीं 3 अन्य घायल हैं. सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना पर सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेज के नोडल ऑफिसर बलराज सिंह ने कहा कि अबतक पांच लोगों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर भेजा है. हम सभी उनकी हालत के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं. अस्पताल ही इस बारे में किसी तरह की जानकारी साझा कर पाएगा. कहा जा रहा हैकि बिल्डिंग में 25 से 30 लोग हताहत हो सकते हैं. मौके पर 17 से ज्यादा एंबुलेंस तैनात की गई हैं.

अपनी कमियां छिपाने के लिए विपक्ष पर सवाल', खरगे ने PM मोदी पर कसा तंज

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (5 सितंबर 2026) को दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी SRCC के शताब्दी समारोह में शामिल हुए. इस कार्यक्रम में उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और विपक्ष पर भी निशाना साधा. अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर प्रतिक्रिया दी है. खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि SRCC में प्रधानमंत्री का जाना युवाओं, शिक्षा और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों पर बातचीत का अच्छा मौका था, लेकिन उनके मुताबिक, युवाओं के सवालों पर चर्चा करने के बजाय कार्यक्रम का भाषण राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित हो गया.मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष पर अलग-अलग तरह के विशेषण लगाए जाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी कथित नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए हर साल विपक्ष के लिए नए नाम इस्तेमाल करती है. खरगे ने अपनी पोस्ट में 'नाराज़ फूफा', 'दिमाग़ी नक्सल', 'अर्बन नक्सल', 'खान मार्केट गैंग', 'आंदोलनजीवी' और 'परजीवी' जैसे शब्दों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि नाम और विशेषण बदल सकते हैं, लेकिन उनके अनुसार मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों में बदलाव नहीं आया है. कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री की युवाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश पर भी तंज कसा।

ISRO निजीकरण की चर्चा को लेकर कर्मचारियों की बढ़ी चिंता

नई दिल्ली। स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोले जाने को लेकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) के कर्मचारियों को अब चिंता सताने लगी है. ISRO के हजारों कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 9 संगठनों ने स्पेस एजेंसी के मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल कामों को प्राइवेट करने के प्रस्ताव पर आधिकारिक स्पष्टीकरण मांगा है. कर्मचारी संगठनों ने ISRO के चेयरमैन वी. नारायणन को पत्र लिखकर एजेंसी के निजीकरण की दिशा, मौजूदा कर्मचारियों और एजेंसी की भविष्य की भूमिका पर इसके असर को लेकर सवाल उठाए हैं.

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह चिट्ठी ISRO के GSLV रॉकेट से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट (पृथ्वी पर नजर रखने वाला उपग्रह) को कई महीनों के अंतराल के बाद सफलतापूर्वक लॉन्च करने के कुछ ही घंटों बाद भेजी गई थी. ISRO के कई सेंटर्स की कर्मचारी यूनियनों ने इस लेटर पर साइन किए हैं.

लेटर पर जिन यूनियन के साइन हैं, उनमें ISRO स्टाफ़ एसोसिएशन, SHAR एम्प्लॉईज़ एसोसिएशन, ISAC एम्प्लॉईज़ एसोसिएशन, ISRO स्टाफ़ एसोसिएशन-LPSC, ISRO स्टाफ़ एसोसिएशन-BBU, NRSA एम्प्लॉईज़ यूनियन, स्पेस एम्प्लॉईज़ एसोसिएशन-BBU, ISRO स्टाफ़ एसोसिएशन-IPRC और SAC एम्प्लॉईज़ वेलफ़ेयर एसोसिएशन शामिल हैं.

फरवरी 2022 के बाद पहली बार खुला यूक्रेन का एयरस्पेस

नई दिल्ली। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच एक अहम घटनाक्रम सामने आया है. फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन का एयरस्पेस सीमित समय के लिए खोला गया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद हवाई मार्ग से यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए रवाना हुए हैं. दोनों देशों की राजधानियों मॉस्को और कीव पर अगले 72 घंटे तक हमले रोकने की सहमति के चलते यह हवाई यात्रा संभव हो सकी है.करीब साढ़े चार साल से यूक्रेन का एयरस्पेस पूरी तरह बंद है. ऐसे में मॉस्को से कीव की हवाई यात्रा को रूस-यूक्रेन शांति वार्ता के लिहाज से अहम घटनाक्रम माना जा रहा है. ट्रंप के दूत मॉस्को और कीव के दौरे पर हैं और इसी दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की राजधानियों पर 72 घंटे तक हमले नहीं करने का फैसला किया है.

फरवरी 2022 से जारी है रूस-यूक्रेन युद्ध

फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था. इसके बाद से दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध जारी है. इस जंग में रूस और यूक्रेन के बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए और घायल हुए हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में आम नागरिकों की भी जान गई है. युद्ध के कारण यूक्रेन ने अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया था. ऐसे में अमेरिकी दूतों का हवाई मार्ग से कीव पहुंचना युद्ध के बाद एक असाधारण घटनाक्रम है.

कांग्रेस ने सचिन पायलट को दी बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली। कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. पार्टी ने गुजरात से पंजाब तक अपने प्रभारी बदले हैं. भूपेश बघेल को पंजाब प्रभारी से हटकर असम का प्रभारी महासचिव बनाया गया. सचिन पायलट को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई. सुखदेव भगत को छत्तीसगढ़ का इंचार्ज बनाया गया. रणदीप सुरजेवाला को प्रभारी महासचिव गुजरात बनाया गया. कांग्रेस की तरफ से प्रेस रिलीज में बताया गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी संगठन में AICC के जनरल सेक्रेटरी / इंचार्ज का कुछ राज्यों में फेरबदल किया गया है. पार्टी ने प्रेस रिलीज में बताया,' भूपेश बघेल को असम का प्रभारी महासिचव बनाया गया है. उनकी जगह पंजाब में सचिन पायलट को प्रभारी महासिचव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला को गुजरात का प्रभारी महासिचव नियुक्त किया गया है. वहीं, सुखदेव भगत को छत्तीसगढ़, डॉ. सिरीवेल्ला प्रसाद को महाराष्ट्र और पीवी मोहन को आंध्र प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है.' इसके अलावा ब्रीफिंग में कहा गया है कि रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक के महासविच प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभालेंगे. इसके अलावा श्री मुकुल वासनिक AICC के महासचिव पद पर बने रहेंगे.

UN ने बदल दुनिया का नक्शा तो US ने किया विरोध

नई दिल्ली। दुनिया के नक्शे में देशों और महाद्वीपों का आकार अक्सर उनकी असली स्थिति से अलग दिखाई देता है. इसे सुधारने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक बड़ा कदम उठाया है. महासभा ने 'Correct the Map' प्रस्ताव को 164-1 के वोट से मंजूरी दे दी. इस प्रस्ताव का मकसद ऐसे नक्शों को बढ़ावा देना है, जिनमें दुनिया के अलग-अलग हिस्सों का क्षेत्रफल ज्यादा सही तरीके से दिखाई दे. हालांकि यह प्रस्ताव सभी देशों के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इससे दुनियाभर में इस्तेमाल होने वाले नक्शों में बदलाव की शुरुआत हो सकती है. भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है. हालांकि भारतीय राजनयिक रघू पुरी ने साफ किया कि भारत ने किसी एक खास नक्शे को सही मानकर इसका समर्थन नहीं किया है. इसमें Equal Earth Projection भी शामिल है. भारतीय राजनयिक रघू पुरी ने कहा कि भारत इस प्रस्ताव को ऐसे नक्शों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के तौर पर देखता है, जिनमें जमीन के असली क्षेत्रफल को सही तरीके से दिखाया जाता है. भारत का समर्थन Equal

Earth Projection या किसी दूसरे खास नक्शे के समर्थन के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कुछ पुराने नक्शों में देशों और महाद्वीपों का आकार उनकी असली स्थिति से काफी बड़ा या छोटा दिखाई देता है. समान क्षेत्रफल वाले नक्शों से इस अंतर को कम किया जा सकता है.रघू पुरी ने कहा कि भारत चाहता है कि इस मामले में किसी एक खास तरीके को थोपने के बजाय देशों, संस्थानों और नक्शे बनाने वाले विशेषज्ञों को अपनी जरूरत के हिसाब से नक्शा चुनने की आजादी हो. उनका कहना था कि नक्शे में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों का आकार ज्यादा सही दिखना जरूरी है.

भारत का कहना है कि ऐसे नक्शों को बढ़ावा मिलना चाहिए, जिनमें अलग-अलग महाद्वीपों और देशों के क्षेत्रफल का असली अनुपात ज्यादा सही नजर आए. रघू पुरी ने कहा कि इससे प्रस्ताव का मकसद पूरा हो सकता है और साथ ही किसी एक खास नक्शे या तकनीक को सबसे बेहतर बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

आज 8वें वेतन आयोग की एक और बड़ी बैठक

कम से कम 58,000 पेंशन की उम्मीद

जयपुर के बाद अब आठवां वेतन आयोग चेन्नई में बैठक करने जा रहा है, जिसमें दक्षिण भारत के कर्मचारी और पेंशनर संगठनों से बातचीत की जाएगी और उनकी तरफ से रखी गई मांगें सुनी जाएंगी.8वें वेतन आयोग के लिए बातचीत की अगली बैठकें 7 सितंबर को चेन्नई में शुरू हो रही हैं. दो दिनों तक चलने वाली इन बैठकों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संगठनों के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित पक्ष वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे. हाल ही में जयपुर में हुई दो दिवसीय बैठक के बाद चेन्नई की यह बैठक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मांगों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है.

चेन्नई में किन मुद्दों पर छिड़ेगी बहस?

पिछली बार की तरह इस बार भी बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा सालाना सैलरी इंक्रीमेंट का होगा. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच मौजूदा 3% का इंक्रीमेंट नाकाफी है. ऐसे में अब यूनियनों ने इसे बढ़ाकर 5% से 7% करने की मांग रखी है, जिससे बेसिक सैलरी में इजाफा हो. कर्मचारी संगठन 7वें वेतन आयोग के 2.57 फिटमेंट फैक्टर के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि मिनिमम बेसिक पे को 18,000 से बढ़ाया जा सके. इस बैठक में पेंशनर संगठनों की ओर से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग के साथ-साथ लेवल 4 से 7 तक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन दरों को बेहतर करने पर गहन चर्चा होगी।

मिनिमम पेंशन में भी हो बढ़ोतरी

8वें वेतन आयोग के तहत पेंशनर्स के लिए पेंशन अमाउंट में भी बढ़ोतरी की मांग है. उनकी मांग है कि नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद लेवल 7 के कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर 58,000 या उससे भी अधिक की बेसिक पेंशन मिल सके. इकोनॉमिक टाइम्स की हालिया रिपोर्ट और पेंशन कैलकुलेशन के फॉर्मूले के अनुसार, यह आंकड़ा पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार अंतिम रूप से कौन सा फिटमेंट फैक्टर तय करती है और कर्मचारी रिटायरमेंट के समय पे-मैट्रिक्स के किस स्टेज पर है. 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 7 (ग्रेड पे 4600 रुपये) की शुरुआती बेसिक सैलरी 44,900 से लेकर अधिकतम 1,42,400 रुपये तक होती है.

सितंबर में बैठकों का पूरा शेड्यूल

7-8 सितंबर 2026- चेन्नई में दक्षिण भारत के कर्मचारी और पेंशनर संगठनों से बातचीत

9 सितंबर 2026- पुडुचेरी में स्थानीय केंद्र शासित प्रदेश के यूनियनों के साथ परामर्श

16-18 सितंबर 2026- चंडीगढ़ में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ के हितधारकों से चर्चा

7-8 अक्टूबर 2026- बेंगलुरु में कर्नाटक क्षेत्र के संगठनों के साथ बैठक

अरुणाचल में भारत-चीन कोर कमांडर की पहली बड़ी बैठक

नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के कोर कमांडर के बीच पहली बड़ी बीपीएम मीटिंग का आयोजन होगा. चीन सीमा पर किबिथू के करीब वाचा-डमई बॉर्डर पर्सनैल मीटिंग (बीपीएम) पॉइंट पर रविवार (6 सितंबर) को मीटिंग होगी. पिछले एक महीने से भारत और चीन की सेनाओं के बीच अपर सुबानसरी इलाके में तनातनी चल रही है. हालांकि भारतीय सेना की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. सूत्रों ने बताया कि पूर्वी सेक्टर में कोर कमांडर स्तर के अधिकारियों के बीच आज पहली बैठक होगी. इस बैठक से इलाके में चल रहे मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी. बता दें कि ये बैठक भारतीय पक्ष की ओर से वाचा बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर आयोजित होगी. चीनी कमांडरों के साथ बैठक में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व 3 कोर कमांडर करेंगे. अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की देखरेख भारतीय सेना के 2 कोर फॉर्मेशन करते हैं, जिनमें तेजपुर स्थित 4 कोर और रंगापहार स्थित 3 कोर शामिल हैं. सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने उस इलाके में चीनी सैनिकों के रुख से निपटने के लिए बहुत ही सख्त रवैया अपनाया है. एक्सपर्ट के मुताबिक भारत और चीन की अपनी-अपनी सीमाओं में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर अलग-अलग समझ है।

FSSAI का नया नियम, स्कूल के 50 मीटर तक नहीं बिकेंगे चिप्स-कोल्ड ड्रिंक्स

नई दिल्ली। आज के समय के बच्चों को घर के खाने से ज्यादा बाहर मिलने वाला जंक फूड खाना पसंद होता है. ऐसे में आपने देखा होगा कि स्कूल के बाहर कई सारी चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स और दूसरे जंक फूड को बच्चे खरीदकर खाते हैं. ऐसे में ये सारी चीजें कम उम्र से ही ज्यादा खाना उनकी सेहत पर असर डाल सकती है. इसी समस्या को देखते हुए खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. दरअसल, FSSAI स्कूल के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की ब्रिक पर रोक लगाने की तैयारी में है, ताकि बच्चे बाहर मिलने वाले जंक फूड को कम खाए. अगर बच्चे बाहर का न खाकर घर का बना हेल्दी खाना खाएंगे तो उनकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी. FSSAI के CEO ने बताया कि स्कूल कैंपस में और उसके 50 मीटर के दायरे में HFSS फूड की बिक्री पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है. FSSAI का मानना है कि अगर बच्चों को स्कूल के अंदर या बाहर ज्यादा जंक फूड उपलब्ध नहीं होंगे तो उनको शुरुआत से ही इन्हें खाने की आदत नहीं पड़ेगी. सबसे जरूरी बात तो यह है कि अभी ये केवल एक प्रस्ताव है.

अमेरिकी इतिहास में सबसे महंगा हुआ डीजल

नई दिल्ली। इस समय केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में महंगाई तेजी से बढ़ रही है. जिससे अमेरिका भी अछूता नहीं रहा है. अमेरिका में भी लगातार महंगाई बढ़ रही है, हाल ही में डीजल की कीमतों में यहां भयंकर इजाफा हुआ है. इसने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. फिलहाल अमेरिका में डीजल की कीमत 5.85 डॉलर प्रति गैलन पहुंच गई है. डीजल महंगा होने से अब रोजमर्रा के सामानों समेत कई और भी चीजें महंगी हो जाएंगी. एसोसिएटेड प्रेस यानी AP की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान और यूएस का जब युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले फरवरी के आखिर में अमेरिका में डीजल की औसत कीमत करीब 3.76 डॉलर प्रति गैलन थी. अब ये बढ़कर 5.85 डॉलर हो गई है. वहीं कच्चे तेल का अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 95 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया है. युद्ध से पहले इसकी कीमत करीब 70 डॉलर प्रति बैरल थी. डीजल की कीमत बढ़ने से केवल आना-जाना की महंगा नहीं होगा बल्कि इससे अन्य चीजें भी महंगी होंगीय साफ शब्दों में कहें तो महंगाई लगातार बढ़ेगी.

केन्या में बंद हुई टाटा की 100 साल पुरानी फैक्ट्री

नई दिल्ली। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा केमिकल्स लिमिटेड को केन्या में बड़ा झटका लगा है. राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कंपनी को मागादी झील में अपना कामकाज बंद करने का आदेश दिया है. खास बात ये है कि इस जगह पर टाटा का कारोबार अभी से नहीं बल्कि पिछले 100 साल से चल रहा है. केन्या में टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा केमिकल्स मगाडी लिमिटेड का कारोबार है. इसका मुख्य काम मागादी झील इलाके से एक प्राकृतिक खनिज ट्रोना निकालना और उसे प्रोसेस करके सोडा ऐश यानी सोडियम कार्बोनेट बनाना है. सोडा ऐश का इस्तेमाल कांच, डिटर्जेंट, केमिकल और पानी की सफाई जैसे कामों में किया जाता है. टाटा का ये कारोबार 1911 में मगाडी सोडा कंपनी के तौर पर शुरू हुआ था. बाद में 2005 में टाटा केमिकल्स ने इसे अपने अधीन ले लिया।

दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईशान किशन ने जड़ा शतक, ठोकी 10वीं सेंचुरी

नई दिल्ली। 2026 दलीप ट्रॉफी का फाइनल ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच खेला जा रहा है. खिताबी मैच में ईस्ट जोन पहले बैटिंग करने उतरी है. पहले दिन ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने पांच नंबर पर खेलते हुए शानदार शतक लगाया. यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका 10वां शतक है. ईशान ने 122 गेंद में सेंचुरी पूरी की. पहले दिन का खेल खत्म होने के समय वह 111 रनों पर नाबाद रहे.

चेपॉक में खेले जा रहे फाइनल मैच में ईशान किशन ने 122 गेंद में शतक पूरा किया. इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके और दो छक्के निकले. पहले दिन का खेल खत्म होने तक उनकी टीम ईस्ट जोन ने 4 विकेट खोकर 385 रन बना लिए हैं. स्टम्प्स के समय ईशान किशन 135 गेंद में 111 रनों पर हैं. वह 14 चौके और 2 छक्के जड़ चुके हैं. कुमार कुशाग्र 75 गेंद में 63 रनों पर नाबाद हैं. वह 4 चौके और 5 छक्के लगा चुके हैं. दोनों के बीच 160 गेंद में 144 रनों की साझेदारी हो चुकी है. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी खिताबी मैच में तेजी से रन बना रहे थे. 37 गेंद में 44 रन बनाकर वह पवेलियन लौटे. उनके बल्ले से 5 चौके और एक छक्का निकला. वहीं उनके साथी ओपनर अभिमन्यू ईश्वरन ने 86 गेंद में 72 रनों की पारी खेली. उन्होंने 10 चौके और एक छक्का लगाया. तीन नंबर पर आए शिखर मोहन ने 120 गेंद में 85 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और 3 छक्के जड़े.

वैभव सूर्यवंशी से भिड़े तिलक वर्मा, स्लेज फिर पंच!

दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने अभिमन्यु ईश्वरन के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी की. 15 वर्षीय बल्लेबाज ने रेड बॉल क्रिकेट में टी20 जैसी पारी खेलकर ईस्ट जोन को तेज तर्रार शुरुआत दिलाई. इस दौरान साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा ने पहले उन्हें स्लेज किया, फिर दोनों के बीच गरमागरमी का माहौल बन गया. मामला बड़ा तो स्थिति को संभालने के लिए अंपायर को बीच-बचाव करना पड़ा. इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. तिलक वर्मा और वैभव सूर्यवंशी के बीच ये बहस 11वें ओवर में हुई. तिलक लगातार वैभव को स्लेज कर रहे थे. उन्होंने वैभव से कहा, 'क्या यार, ये वाइस कैप्टन है।

CPL 2026 में बना बड़ा रिकॉर्ड, एक सीजन में लगे सबसे ज्यादा शतक

नई दिल्ली। सीपीएल 2026 अभी जारी है और एक सीजन में सबसे ज्यादा शतक लगने का रिकॉर्ड बन भी चुका है, जबकि अभी 13 मुकाबले और होने बाकी हैं. कैरेबियन प्रीमियर लीग के 14वें संस्करण में 5 बल्लेबाज सेंचुरी लगा चुके हैं, इसमें 2 एशियाई बल्लेबाज हैं. श्रीलंका के बल्लेबाज अभी तक सर्वाधिक रनों की पारी खेलने वाले बल्लेबाज हैं, एक पाकिस्तानी बल्लेबाज भी इस लिस्ट में शामिल है. सीपीएल 2026 सयुंक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक लगने वाला संस्करण बन गया है. इसके आलावा सिर्फ 2023 में एक सीजन में 5 शतक लगे थे. खास बात ये हैं कि जारी सीजन में अभी सिर्फ 26 मैच ही हुए हैं, जबकि कुल 39 मैच होने हैं. यानी 13 मुकाबले बाकी हैं, एक और शतक लगते ही इतिहास बन जाएगा. कैरेबियन प्रीमियर लीग 2026 में 5 बल्लेबाजों ने शतक लगाए हैं, सभी अलग-अलग फ्रेंचाइजी के हैं. सबसे बड़ी पारी खेलने वाले श्रीलंका के डसून शनका हैं. सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के लिए खेल रहे शनका ने 3 सितंबर को सेंट लुसिया किंग्स के खिलाफ 121 रनों की नाबाद पारी खेली थी.

महिला एशिया कप में भी बवाल, भारत के जीतने पर PCB के नकवी देंगे ट्रॉफी?

नई दिल्ली। शइन दिनों 2026 महिला एशिया कप खेल जा रहा है. बीते शनिवार (05 सितंबर) को टूर्नामेंट का 9वां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला गया. भारत ने 7 विकेट से एकतरफा जीत हासिल की. मैच के बाद एक बार फिर ट्रॉफी को लेकर चर्चा तेज हो गई.

2025 के पुरुष एशिया कप में टीम इंडिया ने खिताब जीता था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं ली थी. यहीं से भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से टॉस और मैच के बाद हाथ मिलाने का सिलसिला खत्म किया था. अब महिला एशिया कप में भी मोहसिन नकवी के ट्रॉफी देने की बात हो रही है.

बता दें कि मोहसिन नकवी PCB के चेयरमैन होने के साथ-साथ एशियाई क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं. इसके चलते वह एशिया कप जीतने वाली टीम को ट्रॉफी सौंपते हैं. लेकिन पिछले साल पुरुष टीम इंडिया ने खिताब जीतने के बाद उनसे ट्रॉफी नहीं ली थी. महिला एशिया कप का फाइनल 13 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोहसिन नकवी फाइनल के मुख्य अतिथि होंगे. इसके अलावा खिताब जीतने वाली टीम को ट्रॉफी भी उन्हीं के हाथों से दी जाएगी.

भारत ने 8.4 ओवर में जीता मैच

नई दिल्ली। श्रीलंका से जुड़ी एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. इस खबर से श्रीलंका क्रिकेट को तगड़ा झटका लगेगा. दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (I C C) ने श्रीलंका से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन ली है. अब किसी नए देश को इस मेगा इवेंट की मेजबानी सौंपी जाएगी. एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है.

आईसीसी ने श्रीलंका से पहली बार होने वाली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी का अधिकार छीन लिया है. नए मेजबान देश को लेकर फैसला आईसीसी की अगली बैठक में लिया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फैसला तब लिया गया जब आईसीसी ने तय किया कि वो श्रीलंका में टूर्नामेंट की मेजबानी के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) को सरकार द्वारा नियुक्त एक अंतरिम प्रशासन चला रहा है.

बता दें कि महिला क्रिकेट में अगले साल पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 14 फरवरी से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 28 फरवरी 2027 को खेला जाना है. इस टूर्नामेंट में कुल छह टीमें हिस्सा लेंगी.

भारत बना यूरोप के लिए डीजल का सबसे बड़ा सप्लायर

नई दिल्ली। ग्लोबल ऑयल मार्केट में भारत का रुतबा बढ़ता जा रहा है. ऐसा हमनहीं कह रहे हैं, बल्कि एनर्जी इंटेलिजेंस फर्म Vortexa के ताजा आंकड़ों (सितंबर 2026) के मुताबिक, अगस्त में यूरोप के लिए बाब-एल-मंडेब से होकर जाने वाले कुल डीजल में से लगभग 60% की सप्लाई अकेले भारत ने की है.

अगस्त 2026 में बाब-अल-मंडेब (Bab-el-Mandeb) समुद्री मार्ग से रोजाना लगभग 2,00,000 बैरल डीजल (गैसऑयल) गुजरा, जबकि मार्च और अप्रैल में इस अहम शिपिंग रूट से होने वाला ट्रांसपोर्ट लगभग रुक गया था. वोर्टेक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस दौरान इस समुद्री मार्ग से होकर यूरोप के लिए जितने भी डीजल की सप्लाई हुई, उसमें भारत की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही. भारत इस मुकाम को हासिल करने में इसलिए कामयाब रहा क्योंकि एक तो रूस से होने वाले एक्सपोर्ट पर भारी रोक लगी हुई है और अमेरिका से होने वाली शिपमेंट भी कम हो रही है।

सस्ती मिल रही प्याज, 4000 टन बफर स्टॉक लाई सरकार

नई दिल्ली। प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों के लिए अब राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने बाजार में प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए अपने बफर स्टॉक से प्याज की रियायती बिक्री शुरू कर दी है. सरकार की ओर से 17 शहरों में अब तक करीब 4,000 टन बफर बेचा जा चुका है. बड़ी बात यह है कि चुनिंदा शहरों में ग्राहकों को प्याज 35 रुपये प्रति किलो की रियायती कीमत पर दिया जा रहा है. सरकार का कहना है कि इस कदम का असर अब बाजार में भी दिखाई देने लगा है और प्याज की कीमतों में कुछ कमी आई है. ऐसे में आने वाले दिनों में नई खरीफ फसल की अवाक शुरू होने के बाद कीमतों में और राहत मिलनी की उम्मीद है.

सरकार ने कितना प्याज स्टॉक कर रखा है?

केंद्र सरकार ने साल 2026 के लिए करीब 1.21 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक तैयार कर रखा है. ऐसे में इस प्याज को जरूरत के हिसाब से अलग-अलग राज्यों और शहरों में भेजा जा रहा है. सरकार अपनी एजेंसियों NCCF और NAFED स्टॉक के जरिए बाजार में प्याज की सप्लाई कर रही है. प्याज को उत्पादक राज्यों से बड़े शहरों तक पहुंचाने के लिए ट्रकों के अलावा 'कंडा एक्सप्रेस' जैसी स्पेशल ट्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है. हालांकि दिल्ली और चेन्नई तक बड़ी मात्रा में प्याज पहुंचाया जा चुका है. अब गुवाहाटी के लिए भी प्याज भेजने की तैयारी की जा रही है.

35 रुपये किलो में कहां मिल रहा प्याज?

सरकार ने कुछ ऐसे शहरों को चुना है जहां प्याज की कीमतें काफी ज्यादा थी. सरकार की ओर से इन जगहों पर बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपये प्रति किलो की रियायती कीमत पर बेचा जा रहा है. NCCF के मुताबिक अब तक करीब 1,500 टन प्याज खुदरा बिक्री के जरिए बेचा जा चुका है.

किन राज्यों में हो रही बफर प्याज की बिक्री?

दिल्ली-एनसीआर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा

7 नामों पर फैसला जल्द

कौन संभालेगा देश की बड़ी तेल कंपनी ONGC की कमान?

नई दिल्ली। सरकारी तेल और गैस कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) को जल्द ही नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिल सकता है. मौजूदा चेयरमैन एवं एमडी अरुण कुमार सिंह का कार्यकाल दिसंबर 2026 में खत्म होना है. इससे पहले सरकार ने उनके उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है. जानकारी के मुताबिक, इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की शुरुआती स्क्रीनिंग के बाद अब सात नाम चयन प्रक्रिया में आगे बढ़े हैं. इन उम्मीदवारों का सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी के सामने इंटरव्यू हो सकता है.

18 उम्मीदवारों में से 7 नाम हुए शॉर्टलिस्ट

चयन प्रक्रिया से जुड़े लोगों के मुताबिक 18 अगस्त को कुल 18 उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की गई थी. इसके बाद दूसरे चरण के लिए सात उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. अब इन्हीं उम्मीदवारों में से ONGC के नए प्रमुख का चयन किया जाएगा. इस रेस में ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत रथ को प्रमुख दावेदारों में माना जा रहा है. 54 वर्षीय रथ ONGC के शीर्ष पद के लिए दूसरी बार कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने पिछले साल भी इस पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन उस समय सरकार ने

अरुण कुमार सिंह का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया था. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में ONGC विदेश लिमिटेड (OVL) के एमडी राजर्षि गुप्ता, ONGC के टेक्नोलॉजी और रीजनल सर्विसेज डायरेक्टर विक्रम सक्सेना, तथा ONGC के स्ट्रैटेजी और कॉर्पोरेट अफेयर्स डायरेक्टर सत्यम कुमार शामिल हैं. इसके अलावा OVL के ऑपरेशंस डायरेक्टर दुलाल हलदर, MRPL के डायरेक्टर (फाइनेंस) देवेंद्र कुमार और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर (मार्केटिंग) एसपी श्रीवास्तव भी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं. इस तरह कुल सात उम्मीदवार ONGC के सबसे बड़े पद के लिए चयन में आगे हैं.

उम्र सीमा में एक बार मिली विशेष छूट

इस बार ONGC के चेयरमैन पद की चयन प्रक्रिया में उम्र की शर्त को लेकर भी काफी चर्चा है. सरकार ने एक बार के लिए अधिकतम उम्र सीमा में बदलाव किया है. इसके तहत ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन का मौका दिया गया, जिनकी उम्र रिक्ति की तारीख यानी 7 दिसंबर 2026 को 59 साल से अधिक नहीं होनी थी. आमतौर पर आंतरिक उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 58 वर्ष और बाहरी उम्मीदवारों के लिए 57 वर्ष बताई गई है. वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अधिकारियों की सामान्य सेवानिवृत्ति उम्र 60 वर्ष होती है. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में राजर्षि गुप्ता का नाम होने के कारण उम्र सीमा को लेकर सवाल उठ रहे हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार 7 दिसंबर 2026 को उनकी उम्र करीब 59 साल और पांच महीने होगी. ऐसे में चयन प्रक्रिया से जुड़े कुछ लोगों का मानना है कि जिन उम्मीदवारों ने उम्र सीमा के कारण आवेदन नहीं किया, वे गुप्ता की नियुक्ति होने पर प्रक्रिया को चुनौती देने की कोशिश कर सकते हैं।

GDP 7.8% हुई, फिर भी आपकी जेब खाली क्यों?

नई दिल्ली। देश की GDP 7.8 प्रतिशत बढ़ गई है. यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है. सवाल यह है कि क्या आपकी सैलरी भी इतनी बढ़ी? राशन, बच्चों की फीस, पेट्रोल और EMI देने के बाद क्या पहले से ज्यादा पैसा बच रहा है? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि GDP का आंकड़ा गलत है. असल बात यह है कि देश की कमाई बढ़ने और उसका फायदा आपकी जेब तक पहुंचने में समय लगता है. भारत की कुंडली भी इसी अंतर की ओर इशारा कर रही है. देश में निवेश और कारोबार बढ़ सकता है, लेकिन नौकरी, वेतन और बचत पीछे रह सकते हैं. नवंबर के बाद दबाव और बढ़ने की आशंका है. अप्रैल से जून 2026 के बीच भारत की वास्तविक GDP 7.8 प्रतिशत बढ़ी. पिछले वर्ष इसी तिमाही में यह दर 6.9 प्रतिशत थी. RBI ने 7 प्रतिशत का अनुमान लगाया था. यानी भारत का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा. लेकिन इस तेजी के पीछे आम लोगों की खरीदारी सबसे बड़ी वजह नहीं है. सड़क, फैक्ट्री, मशीन और दूसरी बड़ी योजनाओं पर होने वाला निवेश 11.9 प्रतिशत बढ़ा. सर्विस सेक्टर में 10 प्रतिशत की तेजी आई. बैंकिंग, रियल एस्टेट, आईटी और प्रोफेशनल सेवाएं 12.1 प्रतिशत बढ़ीं. इसके मुकाबले आम लोगों का खर्च 7.1 प्रतिशत और खेती से जुड़ा क्षेत्र केवल 3.6 प्रतिशत बढ़ा।

'नमस्ते' योजना में छत्तीसगढ़ संयुक्त रूप से देश में प्रथम

शहर सत्ता/रायपुर। सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा स्वच्छता कार्यों में मशीनीकरण को बढ़ावा देने में छत्तीसगढ़ ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार की 'नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम' (NAMASTE) योजना के अंतर्गत राज्यों के प्रदर्शन की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने संयुक्त रूप से देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ के साथ आंध्रप्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश और केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी 'नमस्ते' योजना के क्रियान्वयन में संयुक्त रूप से देश में पहले स्थान पर हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने इस उपलब्धि पर नगरीय निकायों, विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों व 'नमस्ते' योजना के क्रियान्वयन से जुड़े सभी मैदानी अमले को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर कार्य परिस्थितियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वच्छता कार्यों में मशीनीकरण को बढ़ावा देकर जोखिमपूर्ण कार्यों को समाप्त करना और स्वच्छता कर्मियों को सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण कार्य का वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ का 'नमस्ते' योजना के क्रियान्वयन में संयुक्त रूप से राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करना स्वच्छता कर्मियों के सत्यापन, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता, व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था और स्वच्छता कार्यों के मशीनीकरण के लिए यहां किए जा रहे कार्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

आवेदन देते ही 24 घंटे में मिली दिव्यांग बिसंभर को मदद

शहर सत्ता/रायपुर। दो साल पहले एक बस हादसे में घायल में लाचार बिसंभर यादव को महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने महज 24 घंटे में ही मनचाही मदद देकर उसकी जिंदगी आसान की है। आवेदक बिसंभर ने मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े को लिखित पत्र के माध्यम से अपनी समस्या और हालात बताया था। जानकारी के मुताबिक सूरजपुर तहसील जयनगर लटोरी के ग्राम तेलाईकछार निवासी बिसंभर यादव पिता बालगोविंद यादव दो वर्ष पूर्व बिश्रामपुर मंडल का महामंत्री था और प्रधानमंत्री जी के एक कार्यक्रम में जाते समय बस हादसे का शिकार हो गया था। पैरों में गंभीर चोट आई और उपचार के दौरान जान तो बज गई लेकिन विकलांगता की वजह से बिसंभर आर्थिक और शारीरिक रूप से परेशान था। उसने मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से मदद की गुहार लगाई और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए मंत्री ने तत्काल बिसंभर को इलेक्ट्रिक तीन पहिया मोपेड 24 घंटे में दिलवाया।

पीएम आवास ने संवारी कुम्हार मंशाराम की जिंदगी

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से सुदूर वनांचल के अंतिम छोर पर बसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। बालोद जिले के डौण्डी विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम कुमुड़कट्टा में पारंपरिक रूप से कुम्हार का कार्य करने वाले श्री मंशाराम और उनकी पत्नी श्रीमती रामकली का वर्षों पुराना पक्के घर का सपना अब हकीकत में बदल चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिले पक्के मकान ने न सिर्फ उनके परिवार को सुरक्षित छत दी है, बल्कि उनके पारंपरिक हुनर को भी नया संबल प्रदान किया है।

शिक्षक नई पीढ़ी के निर्माता : मुख्यमंत्री

प्रदेश के 63 उत्कृष्ट शिक्षक राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शिक्षक दिवस के अवसर पर आज लोकभवन के छत्तीसगढ़ मण्डपम् में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं को सम्मानित कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। समारोह में वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश के 63 उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चार उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने वर्ष 2026-27 के राज्य शिक्षक सम्मान के लिए चयनित 64 शिक्षकों के नामों की घोषणा भी की।

समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका ने शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में शिक्षा और शिक्षक की भूमिका भी व्यापक हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस दौर में शिक्षकों और विद्यार्थियों का नई तकनीकों से परिचित होना आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी तकनीक का विवेकपूर्ण, जिम्मेदार और मानवीय मूल्यों के अनुरूप उपयोग है। उन्होंने कहा कि AI हमारा सहायक बने, हमारा नियंत्रक नहीं। शिक्षक विद्यार्थियों को तकनीक का उपयोग ज्ञान अर्जित करने, नवाचार करने और अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए प्रेरित करें।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि आज गूगल और डिजिटल तकनीक के माध्यम से हमारे पास सूचनाओं का विशाल संसार उपलब्ध है। इसके बावजूद हमें यह ध्यान रखना होगा कि तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता स्वतंत्र चिंतन और बौद्धिक विकास को प्रभावित न करे। दुनिया के अनेक देशों में विद्यार्थियों द्वारा स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर गंभीर विचार-विमर्श हो रहा है। तकनीक हमें जानकारी उपलब्ध करा सकती है, लेकिन संस्कार, संवेदना, अनुशासन, प्रेरणा और जीवन की सही दिशा गुरु से ही मिलती है। इसलिए बदलते समय में शिक्षक की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक, कौशल आधारित, बहुभाषी और विद्यार्थी-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार किया है। आने वाले समय में शिक्षा के स्वरूप में व्यापक बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसे में शिक्षकों को निरंतर अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन करना होगा। साथ ही विद्यार्थियों की रुचि और प्रतिभा को पहचानकर उन्हें सही विषय और करियर चुनने में मार्गदर्शन देना होगा। विद्यार्थियों की काउंसलिंग भी शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका का हिस्सा है।

राज्यपाल ने कहा कि शिक्षण केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि एक महान और गरिमामय दायित्व है। शिक्षक अपने ज्ञान के साथ-साथ अपने आचरण से भी विद्यार्थियों को शिक्षित करते हैं। बच्चे अपने शिक्षकों को आदर्श के रूप में देखते हैं, इसलिए शिक्षकों को अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ निर्वहन करना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी कैसे आगे बढ़े, उसकी प्रतिभा कैसे निखरे और उसका भविष्य कैसे बेहतर बने, यह शिक्षक की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

अपने विद्यार्थी जीवन की स्मृतियां साझा करते हुए राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि शिक्षक दिवस उन्हें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की अपनी यात्रा की याद दिलाता है। पहले शिक्षक और विद्यार्थी के बीच आदर, आत्मीयता और विश्वास का अत्यंत गहरा संबंध होता था। सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षक पूरी सेवा भावना और समर्पण के साथ विद्यार्थियों का भविष्य संवारते थे।

भगवान श्रीकृष्ण का जीवन हमें धर्म, कर्तव्य और के मार्ग पर चलने की देता है प्रेरणा - मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के टाटीबंध स्थित इस्कॉन रायपुर के श्री श्री राधा रासबिहारी जी मंदिर में आयोजित श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महा-महोत्सव में शामिल हुए। भक्तिमय वातावरण के बीच मुख्यमंत्री श्री साय ने भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना एवं शंख अभिषेक किया और प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि, खुशहाली और मंगलमय जीवन की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों और उपस्थित श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का संपूर्ण जीवन मानव समाज को धर्म, कर्तव्य और लोककल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्रीमद्भगवद्गीता के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण ने कर्मयोग का जो संदेश दिया, वह आज भी मानवता को जीवन की चुनौतियों के बीच अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जन्माष्टमी केवल भगवान श्रीकृष्ण के प्राकट्य का उत्सव नहीं, बल्कि उनके जीवन-दर्शन और आदर्शों को आत्मसात करने का भी अवसर है। भगवान श्रीकृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से अन्याय के विरुद्ध खड़े होने, धर्म की रक्षा करने और समाज के कमजोर वर्ग के साथ खड़े रहने का संदेश दिया। उनके विचार युगों-युगों से भारतीय समाज को प्रेरित करते आ रहे हैं। इस अवसर पर मंदिर परिसर 'हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे' के महामंत्र से गुंजायमान रहा। मुख्यमंत्री श्री साय ने भी भक्तवृंद के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का घोष किया और वृंदावन बिहारीलाल के प्राकट्य उत्सव पर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर में बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं के उत्साह और भक्तिभाव से पूरा वातावरण कृष्णमय हो गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती प्राचीन काल से ही धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की पुण्यभूमि रही है।

छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता की सुगबुगाहट तेज़: दुर्ग संभाग से शुरू होगा जन-संवाद

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी गई है। प्रदेश में UCC का प्रारूप (ड्राफ्ट) तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति अब सीधे ज़मीन पर उतरकर सामाजिक और प्रशासनिक समन्वय साधने में जुट गई है। इसी रणनीति के तहत दुर्ग संभाग के सभी जिलों के प्रमुखों, प्रबुद्ध जनों और जनप्रतिनिधियों के साथ आगामी 8 और 9 सितंबर को एक वृहद समूह चर्चा और परिचयात्मक बैठक आयोजित करने जा रही है। ज्ञात हो कि समान नागरिक संहिता के दूरगामी प्रभावों और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह संवाद प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दो दिनों तक चलने वाले इस मंथन में दुर्ग संभाग के अलग-अलग जिलों को केंद्रित करते हुए बैठकें होंगी। आगामी 8 सितंबर को दुर्ग में दोपहर 12 बजे से आयोजित इस बैठक में दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिले के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसी तरह 9 सितंबर को राजनांदगांव में दोपहर 12 बजे से होने वाली बैठक में राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले का प्रतिनिधित्व रहेगा।

रायगढ़ की बदलेगी तस्वीर

वित्त मंत्री ने किया विकास परियोजनाओं का मैराथन निरीक्षण

शहर सत्ता/रायगढ़/रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना विकास को नई गति मिल रही है। इसी क्रम में रायगढ़ शहर को आधुनिक, सुव्यवस्थित और बेहतर नागरिक सुविधाओं से युक्त शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओ.पी. चौधरी ने शुक्रवार को शहर की प्रमुख विकास परियोजनाओं का मैराथन निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता और समय-सीमा की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसियों को कार्यों में तेजी लाने तथा निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने दूध डेयरी ऑक्सीजोन से निरीक्षण की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने गोवर्धनपुर में केलो नदी पर निर्माणाधीन पुल, खर्राघाट स्थित केलो रिवर फ्रंट, नालंदा परिसर, एसईसीएल रोड मरीन ड्राइव, कयाघाट पुल, मिनी स्टेडियम स्थित स्केटिंग रिंग, कौहाकुंडा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, स्टेडियम और एफसीआई ऑक्सीजोन सहित विभिन्न विकास कार्यों का स्थल निरीक्षण किया।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि रायगढ़ के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, इंजीनियरों और निर्माण एजेंसियों के समन्वय से लगातार कार्य किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य केवल निर्माण कार्य कराना नहीं, बल्कि शहर की अधोसंरचना को मजबूत करते हुए नागरिकों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना है। प्रत्येक परियोजना की गहन निगरानी की जा रही है, ताकि विकास कार्य तेजी के साथ उच्च गुणवत्ता में पूरे हों।

टेक्सटाइल सेक्टर में प्रदेश के लिए बड़ी संभावनाएं, केंद्र करेगा हरसंभव सहयोग

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के टाटीबंध स्थित इस्कॉन रायपुर के श्री श्री राधा रासबिहारी जी मंदिर में आयोजित श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महा-महोत्सव में शामिल हुए। भक्तिमय वातावरण के बीच मुख्यमंत्री श्री साय ने भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना एवं शंख अभिषेक किया और प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि, खुशहाली और मंगलमय जीवन की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों और उपस्थित श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का संपूर्ण जीवन मानव समाज को धर्म, कर्तव्य और लोककल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्रीमद्भगवद्गीता के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण ने कर्मयोग का जो संदेश दिया, वह आज भी मानवता को जीवन की चुनौतियों के बीच अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जन्माष्टमी केवल भगवान श्रीकृष्ण के प्राकट्य का उत्सव नहीं, बल्कि उनके जीवन-दर्शन और आदर्शों को आत्मसात करने का भी अवसर है। भगवान श्रीकृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से अन्याय के विरुद्ध खड़े होने, धर्म की रक्षा करने और समाज के कमजोर वर्ग के साथ खड़े रहने का संदेश दिया। उनके विचार युगों-युगों से भारतीय समाज को प्रेरित करते आ रहे हैं। इस अवसर पर मंदिर परिसर 'हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे' के महामंत्र से गुंजायमान रहा। मुख्यमंत्री श्री साय ने भी भक्तवृंद के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का घोष किया और वृंदावन बिहारीलाल के प्राकट्य उत्सव पर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर में बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं के उत्साह और भक्तिभाव से पूरा वातावरण कृष्णमय हो गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती प्राचीन काल से ही धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की पुण्यभूमि रही है। यह माता कौशल्या का मायका और प्रभु श्रीराम का ननिहाल है। हमारे गांवों, नगरों, मंदिरों, तीर्थों और लोक परंपराओं में हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जीवंत है।

सड़कों पर घूमते मवेशी दावों के बीच सिस्टम लाचार

रायपुर (शहर सत्ता)। छत्तीसगढ़ के शहरों से लेकर गांवों तक की सड़कें इन दिनों विकास या यातायात की सुगमता के लिए नहीं, बल्कि सड़क पर डेरा जमाए मवेशियों के लिए चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में मुख्य मार्गों से लेकर गली-मोहल्लों तक मवेशियों का खुलेआम घूमना और बीच सड़क पर बैठना आम बात हो गई है। इसके कारण जहां एक ओर आए दिन लंबा जाम लग रहा है, वहीं दूसरी ओर आम जनता की जान का जोखिम भी बढ़ गया है।

जाम और हादसों का बनता सबब, दावों के बीच सुस्त पड़ी प्रशासनिक मशीनरी

रायपुर में हर 54 नागरिकों पर एक गाय, प्रशासनिक दावों की खुली पोल

रायपुर के आंकड़े बयां कर रहे हैं भयावह स्थिति

रायपुर में आवारा गायों और बैलों का तांडव इस हद तक बढ़ चुका है कि हर 54 नागरिकों पर लगभग एक सड़क पर घूमने वाली गाय है। पूरे शहर में इनकी आबादी करीब 35,000 तक पहुंच चुकी है।

- रिंग रोड और ब्लैक स्पॉट्स बने मौत के कुएं: रिंग रोड नंबर 3 और पिरदा चौक (बिलासपुर रोड से विधानसभा होते हुए मंदिर हसौद मार्ग) पर स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। भारी वाहनों और तेज रफ्तार ट्रकों की चपेट में आने से केवल एक हफ्ते के भीतर यहाँ 28 गायों की दर्दनाक मौत दर्ज की गई है।
- प्रमुख हादसे के क्षेत्र: पिरदा चौक, संतोषी नगर, मथपुरैना रिंग रोड, भाटागांव, पेंशनबाड़ा, बूढ़ापारा और लाखेनगर जैसे व्यस्त इलाकों में अचानक मवेशियों के सामने आने से वाहन चालक गंभीर हादसों का शिकार हो रहे हैं।
- सिर्फ रायपुर नहीं, पूरे प्रदेश का यही हाल: जीपीएम (GPM) जिले के गौरेला में मवेशियों के कारण हुए हादसों में 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।

हमारे शहर के लिए आवारा मवेशियों की समस्या गंभीर है और इसके लिए सभी जोन कमिश्नर को सख्त निर्देश दिए गए हैं। कई बार नगर निगम सड़क से पशुओं को उठाता है, तो पशुपालक उन्हें वापस मांगने आ जाते हैं। ऐसे में अब नियमों को और सख्त करते हुए फाइन (जुर्माना) को बढ़ाया जाएगा।"

- मीनल चौबे, महापौर रायपुर नगर निगम

बड़ा सवाल: कब मिलेगी निजात?

प्रशासनिक बैठकों, सख्त निर्देशों और बढ़े हुए जुर्माने की चेतावनियों के बावजूद यह सवाल आज भी जस का तस बना हुआ है—आखिर कब छत्तीसगढ़ की सड़कों को आवारा मवेशियों के आतंक से मुक्ति मिलेगी और कब आम जनता सुरक्षित सफर कर पाएगी?

कार्रवाई बनाम धरातल की हकीकत

नगर निगम और प्रशासन द्वारा मवेशियों को पकड़ने और पशुपालकों पर नकेल कसने के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आती है:

- **काऊ कैचर अभियान और जुर्माने की तैयारी:** हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद नगर निगम की टीमें सभी 10 जोनों में अभियान चला रही हैं। हाल ही में भाटागांव से 9 और संतोषी नगर-मथपुरैना से 13 मवेशी पकड़े गए हैं। हालांकि, पशुपालकों पर चालानी कार्रवाई का कोई खास असर नहीं हो रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन अब जुर्माने की राशि को और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।
- **दावों की पोल खुद मेयर निवास के बाहर:** कागजी निर्देशों और धरातल के बीच जमीन-आसमान का फर्क है। जोन कमिश्नर को दिए गए निर्देशों का असर कितना है, इसकी बानगी खुद महापौर निवास के बाहर देखी जा सकती है, जहां दोपहर के वक्त बीच सड़क पर मवेशी आराम फरमाते डेरा जमाए नजर आते हैं।
- **योजनाएं और अभियान फेल:** स्थानीय लोगों का कहना है कि कागजी आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिलता। मवेशी शिफ्टिंग के दावे कागजों तक सीमित हैं, और काऊ कैचर गाड़ियां कभी-कभार ही नजर आती हैं।

राजनीतिक सरगर्मी और कांग्रेस का प्रदर्शन

इस गंभीर मुद्दे पर लंबे समय से सियासत हो रही है, लेकिन नतीजा आज तक नही निकल पाया है। इस समस्या की ओर सरकार का ध्यानाकर्षण करने के लिए कांग्रेस ने जहां प्रदेशभर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पूर्ववर्ती सरकार की 'गौठान योजना' को दोबारा शुरू करने की जोरदार मांग उठाई गई, ताकि गायों का सही तरीके से रख-रखाव सुनिश्चित किया जा सके और उन्हें सड़कों पर भटकने से रोका जा सके।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.),
मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)। डाक पंजीयन - CG/RYP/DN/70/2025-27